



दिल दहलाने वाला हादसा

पुष्पक एक्सप्रेस में 'चिंगारी' से डरकर कूदे यात्री

दूसरी तरफ से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस ने कुचला, 11 की मौत,

जलगांव। महाराष्ट्र के जलगांव में बुधवार को भीषण ट्रेन हादसा हो गया। जलगांव के परांदा रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अपवाह फैल गई, जिसके बाद यात्री नीचे ट्रैक पर कूद गए, तभी सामने से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस ने लोगों को कुचल दिया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि हादसे में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और 40 यात्री घायल हो गए। यह भयावह रेल दुर्घटना बुधवार को शाम 4.19 बजे परांदा रेलवे स्टेशन के पास हुई। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह हादसा तब हुआ जब पुष्पक एक्सप्रेस में सवार यात्री ट्रेन के पहियों से धुआं निकलने के बाद आग लगने की आशंका से बचने के लिए जल्दबाजी में पटरियों पर कूद गए। यह ट्रेन लखनऊ से मुंबई जा रही थी। यात्रियों के अचानक पटरियों पर आ जाने से यह हादसा हुआ। उसी समय, दूसरी तरफ से कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही थी, पटरी पर कूदे यात्री ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे में मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। मध्य रेलवे के मुख्य प्रवक्ता स्वर्णिम नीला ने कहा कि पुष्पक एक्सप्रेस के कुछ यात्री नीचे उतर गए थे और सामने से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए, जिस कारण यह हादसा हुआ।



जलगांव जिले के एसपी महेश्वर सिंह रेड्डी ने बताया कि हादसे में 11 लोगों की मौत हुई है और 5 लोगंगा घायल हुए। उन्होंने बताया कि घायलों को पुष्पा एक्सप्रेसता लें जाया गया है, जबकि शव जलगांव भेजे गए हैं।

कोच के अंदर चिंगारी उठी

घटना जलगांव और पचौरी स्टेशन के बीच की है। पुष्पा एक्सप्रेस (12533) मुंबई की ओर जा रही थी, जबकि कर्नाटक एक्सप्रेस (12627) दिल्ली की दिशा में चल रहा जा रहा है कि पुष्पा एक्सप्रेस के नीचे से धुआं निकलता नजर आया, जिसके बाद हादसा अफवाह फैल गई कि ट्रेन में आग लग गई है। डर के मारे कई यात्री चलाती ट्रेन से कूद पड़े। हालाँकि, रेलवे अधिकारियों का कहना है कि गमों के कारण धुआं निकल



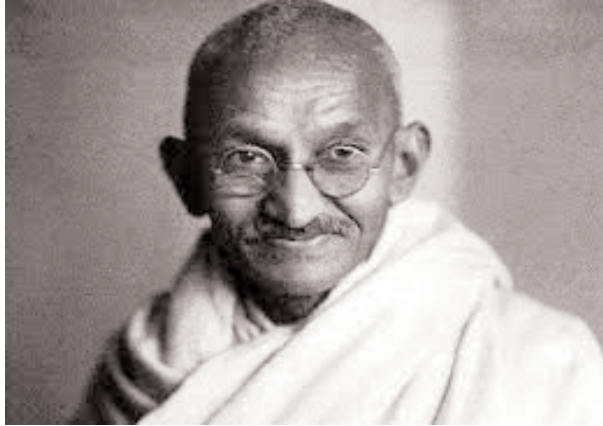
सकता है लेकिन यह आग नहीं थी। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक पुष्पक एक्सप्रेस के एक कोच के अंदर हॉट एक्सल्ट या ब्रेक-बाईंडिंग के कारण चिंगारी उठी और कुछ यात्री घबरा गए। यात्रियों ने चेन खींच दी और कूद गए चिंगारी और धुआँ देखकर यात्री घबरा गए। उन्होंने चेन खींच दी, और उनमें से कुछ नीचे कूद गए। उसी समय कर्नाटक एक्सप्रेस बागल के ट्रैक से गुजर रही थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन का कहना है कि जलगांव जिले के कलेक्टर के मुताबिक हादसे में 10 से 12 यात्रियों की मौत हुई है। वहीं रेलवे के डिवीजनल कमिश्नर

प्रवीण गेदम ने बताया कि हादसे में 11 यात्रियों की मौत हो गई। रेवले अधिकारियों के मुताबिक यह आग थी या कोई अन्य अफवाह, हम जांच कर रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी से संकेत मिलता है कि ट्रेन में कोई आग नहीं थी।

इसलिए कर्नाटक एक्सप्रेस को नहीं देख सके लोग सेंट्रल रेलवे के भुसावल डिवीजन के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जहाँ हादसा हुआ, उस जगह पर शाप्ट टर्न था। इस वजह से दूसरे ट्रेक पर बैठे पैसेंजर्स को ट्रेन के आने का अंदाजा नहीं लगा। यहीं वजह रही कि कर्नाटक एक्सप्रेस से इतनी बड़ी संख्या में लोग कूचले गए।

पूष्पक एक्सप्रेस के बी-4 कोच में हुई स्पाकिंग जानकारी के मुताबिक लखनऊ से मुंबई आ रही पूष्पक एक्सप्रेस ट्रेन के बी-4 कोच में स्पाकिंग होने पर उसी सॉफ्ट गया था। यह स्पाकिंग शॉर्ट-टर्म की वजह से नहीं हुआ बल्कि हाँट एक्सेल या ब्रेक बाइंडिंग के चलते हुआ। इस कारण बी-4 कोच के पहियों से चिंगारियाँ निकली और धुआँ उठा। यात्रियों को लगा कि ट्रेन में अगल जा रही है। करीब 50 से 60 यात्री अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन से दूसरी ओर के ट्रैक पर कूद गए। घटनास्थल मुंबई से 400 किलोमीटर दूर है।

मप्र में 30 जनवरी को दो मिनट के लिए सभी को रहना होगा मौन



अन्य गतिविधियों को रोक दिया जाना चाहिए। आदेश में आगे कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि कुछ कार्यालयों में तो दस मिनट का मौन रखा जाता है लेकिन आम जनता अपने काम में लगी रहती है। इस अवसर के दौरान गंधीरात्रि पर ध्यान नहीं देती है इसलिए अनुरोध है कि शहीद दिवस को पूरी गंधीरात्रि के साथ

मनाया जाए। आदेश में यह भी कहा गया है कि आपके (आयुक्तों और कलेक्टरों) नियंत्रणाधीन सभी शिक्षण संस्थाओं और सार्वजनिक उपक्रमों को निर्देश जारी किए जाने चाहिए कि शहीद दिवस पूरी गंभीरता से मनाया जाए। स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय एकता पर चर्चा और भाषण हाइब्रिड मोड में आयोजित किए जाने चाहिए।

15 दिन से मुर्दाघर में पड़ा है शव, दफनाने को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई

नई दिल्ली। 15 दिन से मुर्दाघर में रखा एक शव दफनाए जाने का इंतजार कर रहा है। वजह है दफनाए जाने को लेकर विवाद। विवाद इस पर कि कहां दफनाया जाए। मृतक के बेटे की इच्छा है कि उनके पिता को गांव के कब्रिस्तान में दफनाने की जाजनात दी जाए। मामला छत्तीसगढ़ का है। मृतक धर्मांतरित ईसाई थे। इसका गांव के आदिवासी विरोध कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आदिवासियों के कब्रिस्तान में ईसाई शवों को नहीं दफनाने देंगे। मामला अदालत पहुंच गया। शव मुर्दाघर में पड़ा हुआ है। हाईकोर्ट ने आदिवासियों के कब्रिस्तान में ईसाई शवों को दफनाने की इजाजत नहीं दी। मृतक के बेटे उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। शीर्ष अदालत में छत्तीसगढ़ सरकार ने दलील दी है कि आदिवासी हिंदुओं के कब्रिस्तान में ईसाई शवों को दफनाए जाने से परेशानी



होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अब अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मृतक एक धर्मांतरित इंडीयां थे जो पादरी के तौर पर काम करते थे। 7 जनवरी को उनका निधन हो गया। मृतक के बेटे रमेश बघेल अपने पिता को पैतृक गांव छिंदवाड़ा में उस कब्रिस्तान में दफनाना चाहते हैं जहां उनके पूर्वज दफनाए गए हैं। छिंदवाड़ा बस्ती जिले का एक गांव है। गांव वाले

ईसाई शख्स को हिंदू आदिवासियों के लिए बने कब्रिस्तान में दफनाने का विरोध कर रहे हैं। इसके बाद बघेल ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने भी प्रजापंथ नहीं दी। 7 जनवरी से ही शख्स का शव मुदांधर में पड़ा हुआ है। मृतक के बेटे ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिस पर कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

सीएम मोहन यादव ने पुणे में उद्योगपति और निवेशकों के साथ इंटरैक्टिव सेशन में की सीधी बात, कहा- मप्र में विकास की अपार संभावनाएं

मप्र का होगा औद्योगिकीकरण

पोपाल। पुणे में निवेशकों की बैठक पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मुझे खुशी है कि मध्यप्रदेश सरकार अपने सभी विभागों के माध्यम से मध्यप्रदेश के औद्योगिकीकरण के लिए जगह पर काम कर रही है। अब जब हम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 24 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट करने जा रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में बड़े घरानों को आमंत्रित करें और सभी प्रकार की संभावनाओं पर काम करें। उसी संबंध में मुंबई, बैंगलुरु, कलकत्ता जैसे कई शहरों में मैंने दौरा किया। मुंबई के बाद पुणे महाराष्ट्र में एक बड़ी जगह है, जहां पर कई क्षेत्रों के बड़े-बड़े खिलाड़ी या निवेशक वहां पर मिलते हैं, वे हमारे औद्योगिकीकरण अभियान का हिस्सा बनें। मैं उन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूँ और आशा करता हूँ कि परिणाम बहुत अच्छे होंगे। सीएम मोहन यादव ने पुणे में बुधवार को निशे-माने उद्योगपति और निवेशकों के साथ इंटरैक्टिव सेशन में शिरकत की। सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक हमने अपने राज्य में इंदौर, कांकेर, इन्वेस्टर्स समिट में अजय मध्यप्रदेश बहुत आगे बढ़ चुका है। इंदौर अब ग्लोबली रूप से अलग महत्व रखता है, जो स्वच्छता में सात बार से अपनी साख बनाए हुए है।

पीथमपुर और मंडीदीप बहुत आगे बढ़ चुके मुख्यमंत्री ने कहा कि पीथमपुर और मंडीदीप उद्योग के मामले में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और रजनील कॉन्क्लेव के माध्यम से हमने प्रदेश के हर हिस्से तक निवेश के रूप में विकास पहुंचाने का प्रयास किया। सीएम ने कहा कि मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। पुणे और मध्यप्रदेश के शहरों के बीच आवागमन का महत्व इस रिश्ते को और प्रगाढ़ बनाता है। डेड सी से



अधिक वीडियो कोच बसें और नियमित उड़ानें यह दर्शाती हैं कि दोनों राज्यों के बीच कितना प्रेम और सहयोग है।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र ने राष्ट्रवाद की प्रेरणा दी और बाबा महाकाल की आस्था में भी महाराष्ट्र का योगदान है। अहिल्या माता की 3000वीं जयंती पर मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के बीच जुड़वा का एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ रहा है। अहिल्या माता ने शासनकाल में किसानों और आजीविका के लिए एक उज्ज्वल दाहरण प्रस्तुत किए।

PM देश का प्रमुख केंद्र बनेगा

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में छोटे-छोटे इन्वेस्टर समिट्स के जरिये निवेशकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इंदौर न केवल स्वच्छता की राजधानी बन चुका है, बल्कि व्यापार का भी प्रमुख केंद्र है। पीथमपुर और मंडीदीप जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में विकास की अपार संभावनाएं हैं।

उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि राज्य सरकार और औद्योगिक विकास के लिए हर संभव कदम उठा रही है और आने वाले समय में उद्योगों के लिए महाराष्ट्र देश का प्रमुख केंद्र बनेगा। डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सभी सेक्टर में निवेश के लिए हमने आकर्षक पॉलिसी बनाई है, एजुकेशन, फार्मा, माइनिंग, मेडिकल, आईटी, टूरिज्म के क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं।

मध्यप्रदेश में श्रम आधारित समस्या नहीं है और तकनीक के माध्यम से आप कहीं से भी व्यवसाय का संचालन कर सकते हैं।

उद्योगपतियों की भूमिका

महत्वपूर्ण सीएम मोहन यादव ने उद्योगपतियों की प्रशंसा में कहा कि जिस प्रकार सीमा पर जवान अगर देश की रक्षा करता है तो अपने कुशल कौशल और व्यवसाय के माध्यम से देश को मजबूत करने में उद्योगपतियों की भी भूमिका होती है। उद्योगपति कई लोगों को रोजगार दे रहे हैं तो भारत को स्वाभिमान के साथ नंबर वन बनाने की भूमिका भी निभा रहे हैं। सीएम ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। हमने इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को भी पीछे छोड़ दिया। 11वीं अर्थव्यवस्था से हमें पाँचवीं आर्थिक शक्ति बन चुके हैं। इसी का परिणाम है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथग्रहण समारोह में ही भारत की ताकत और महत्व का अंदाजा हो गया जब डाइयस के सामने हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद मौजूद थे। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने उद्यमशीलता को सुशासन के साथ बढ़ावा दिया है। जो रूस के राष्ट्रपति के गले मिल रहे हैं तो यूक्रेन का सफर भी ट्रेन से कर रहे

आज से महाकाल की
मस्म आरती के समय
नहीं ले जा सकेंगे
मोबाइल

उज्जैन। अगर आप विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में सुबह 4 बजे होने वाली भस्म आरती के दर्शन करने जा रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है, क्योंकि गुरुवार 23 जनवरी से महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती करने आने वाले श्रद्धालुओं के मंदिर में मोबाइल ले जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लग दिया गया है। अगर श्रद्धालुओं को भस्म आरती देखने के लिए पहले अपने मोबाइल की महाकालेश्वर प्रबंध समिति के पास जमा करवाने होंगे, उसके बाद ही वे भस्म आरती देख पाएंगे। महाकालेश्वर मंदिर के प्रशासक अनुकूल जैन ने कुछ ऐसे ही निर्देश जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने भस्म आरती में मोबाइल ले जाने पर श्रद्धालुओं के लिए प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध लगाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने के साथ ही यहां पर रील भी शूट करते हैं। महाकाल मंदिर परिसर और यो फिर महाकाल लोक श्रद्धालु इन स्थानों पर फिल्मी गानों में रील बनाते हैं और खुद की प्लिंसिटि के लिए इन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर अपलोड भी करते हैं। जिससे इन लोगों को भले ही प्रसिद्धि मिलती हो लेकिन इससे श्री महाकालेश्वर मंदिर की प्रतिष्ठा जरूर धूमिल होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रशासक अनुकूल जैन ने गुरुवार से भस्म आरती में श्रद्धालुओं द्वारा मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। याद रहे कि महाकाल मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा ने मंदिर परिसर और महाकाल लोक में बनाई जाने वाली रील को लेकर कड़ी आपत्ति ली थी और कहा था कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालु इस स्थान को धार्मिक स्थल तो समझते हैं लेकिन कुछ श्रद्धालुओं ने इसे पर्टन क्लश भी समझ लिया है यही कारण है कि यहां भगवान की प्रतिमाओं के सामने फिल्मी गानों पर रील बनाई जाती है जो कि गलत है।

सेना के तोपखाने की कर्तव्यपथ पर दिखेगी ताकत, स्वदेशी पिनाका भी दिखेगा



है दिल्ली। गणतंत्र दिवस परेड में
 कर्तव्यपथ पर भारतीय सेना के
 तोपखाने की ताकत भी दिखेगी।
 भारतीय सेना के पास तीन तरह के
 भारतीय बैरल रॉकेट हैं- रूसी ग्रेड,
 स्मर्च और स्वदेशी पिनाका
 (अग्निबाण)। परेड में कर्तव्य पथ
 पर पिनाका मॉडलॉन्च रॉकेट
 सिस्टम और ग्रेड रॉकेट लॉन्चर
 दिखाई देगा। ग्रेड इस बार अपने
 नए अवतार में होगा। भारतीय सेना
 में करगिल युद्ध के वक़्त पिनाका
 मॉडल बैरल रॉकेट (अग्निबाण)
 लॉन्च होना शुरू हुआ था। यह
 स्वदेशी है। इसका कैलिबर
 1214एमएम है। इसकी रेंज 40
 किलोमीटर है। पिनाका के हर
 रॉकेट लॉन्चर में 12 रॉकेट होते हैं।
 पिनाका की एक बैटरी में 6
 वीइकल यानी 72 रॉकेट होते हैं।
 एक बैटरी 44 सेकंड में 72 रॉकेट
 दाग सकती है। पिनाका रॉकेट की
 रेंज बढ़ाने पर काम चल रहा है। 75
 किलोमीटर रेंज वाले पिनाका रॉकेट
 का परीक्षण हो चुका है और इसे
 भारतीय सेना में शामिल करने की
 तैयारी है। इसकी रेंज 90
 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और
 300 किलोमीटर तक करे की भी

प्लानिंग है। भारतीय सेना के पास अभी पिनाका की चार रेजिमेंट हैं। 6 और रेजिमेंट को मंजूरी मिल चुकी है।

पुराने ग्रेड की गाड़ी को नया किया गणतंत्र दिवस परेड में इस बार नया ग्रेड रॉकेट लॉन्चर दिखाया, वह नया अवतार में होगा। भारतीय सेना में पुराने ग्रेड की गाड़ी को नया कर दिया है। ग्रेड मल्टीबैरल रॉकेट लॉन्चर पहले रूसी वीइकल वा' 375 पर था। यह कैरियर पुराना हो गया है। भारतीय सेना ने नया वीइकल को बदल दिया है और इसकी जगह पर अशोक लीलैंड का ट्रक लगाया है। इसलिए कर्तव्य पर जो ग्रेड इट-21 दिखाई देगा उसका लॉन्चर तो पुराना ही है लेकिन कैरियर नया है।

40 साल पहले रूस से खरीदी थीं ग्रेड तत्कालीन 40 साल पहले भारत ने रूस से ग्रेड खरीदी थी। इसका इस्तेमाल करगिल युद्ध में खूब किया गया कर सकती है। इसका कैलिबर 122 एएमए है यानी इससे 122 एएमए के रॉकेट फायर किए जाते हैं। एक लॉन्चर में 40 रॉकेट होते हैं।

शादी से इनकार करना
आत्महत्या के लिए
उकसाने वाली बात नहीं

नहीं दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आत्महत्या से जुड़े केस में अहम टिप्पणी की है। अदालत का कहना है कि शादी के लिए असहमति जताना ही आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध का आधार नहीं हो सकता। उच्चतम न्यायालय ने हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है और अपीलकर्ता को राहत दी है। जस्टिस एनवी नारगना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। अपीलकर्ता मां और युवक के परिवार के अन्य सदस्यों पर युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगे थे। अदालत ने कहा कि अगर अपीलकर्ता ने बाबू दास और उसकी प्रेमिका की शादी को लेकर आपत्ति जताई थी, तो भी आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप के स्तर तक नहीं पहुंचता है। अदालत ने यह भी कहा है कि मुकासे या यह कहना है कि अगर वह प्रेमी से शादी के बेगर नहीं रह सकती, तो भी इसे आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता है। खास बात है कि ट्रायल कोर्ट की तरफ से भी अपीलकर्ता जिसका कोरा राहत नहीं मिली थी, मिसाले बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी आदेश को बरकरार रखा था। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट का रुख थिया गया। सुनवाई के दौरान शीर्ष न्यायालय ने पाया है कि अपीलकर्ता और उसके परिवार ने मुत्ता के बाबू दास और उसके बीवी रिश्ते पर खूब करने के लिए दबाव नहीं डाला है। कोर्ट ने कहा कि बल्कि, मुत्ता का परिवार ही था, जो रिश्ते से खुश नहीं था। कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता की तरफ से उठाए गए कदम किसी भी तरह से आर्टिफीसली भारतीय उद्द सहित की धारा 306 को आकषिप्त नहीं करते हैं। साथ ही ऐसे भी कोई आरोप नहीं है, जो यह दिखाते हों कि मुत्ता के पास आत्महत्या जैसा कदम उठाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था।

इंदौर में मेट्रो ट्रेन का हुआ सेफ्टी ऑडिट

कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी ने सुरक्षा मानकों को परखा, अप्रुवल के बाद होगा कमर्शियल रन

सिटी चीफ इंदौर। इंदौर। इंदौर में मेट्रो स्टेशन, कोच का सेफ्टी ऑडिट हो गया है। इसके लिए कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी (सीएमआरएस) की टीम इंदौर मंगलवार को ही आ गई थी। बुधवार सुबह अफसर गांधी नगर डिपो पहुंचे और सुरक्षा मानकों के हिसाब से मेट्रो कोच को परखा। इसके अलावा डिपो में संचालन से जुड़ी गतिविधियों को देखा। मेट्रो के लिए बनाए सेंटर की भी जांच की गई। इसके बाद अब सिविल वर्क का ऑडिट होगा। उसके लिए टीम 26 जनवरी के बाद आएगी। सेफ्टी ऑडिट में तय मापदंडों पर परखे जाने के बाद सीएमआरएस की तरफ से मेट्रो के संचालन की मंजूरी मेट्रो रेल कांफोरिशन को मिलेगी। इस प्रक्रिया में डेढ़ माह का समय लग सकता है। उसके बाद कमर्शियल रन होगा। बुधवार को आई टीम ने



कांफोरिशन के अफसरों के साथ बैठक की और आवश्यक जानकारी जुटाई। मेट्रो के कोच के बारे में जानकारी ली। इसके बाद मेट्रो

हिस्से में काम चल रहा है। मेट्रो एयरपोर्ट से सुपर कॉरिडोर, विजय नगर, खजराना रिंग रोड, तिलक नगर, पलासिया, गांधी प्रतिमा, राजवाड़ा, सदरबाजार, बड़ा गणपति, एरोड्रम रोड होते हुए एयरपोर्ट तक जाएगी। नाथ मंदिर रोड से एरोड्रम रोड तक मेट्रो भूमिगत रहेगी। फिलहाल इसका काम शुरू नहीं हो पाया है। पहले 17 किलोमीटर हिस्से में ट्रायल रन का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया है। इस कारण अभी छह किलोमीटर हिस्से में मेट्रो का संचालन शुरू करने की तैयारी की गई है, हालांकि इस हिस्से में मेट्रो के लिए यात्री काफी कम मिलेंगे। अब सीएमआरएस से ग्रीन सिग्नल का इंतजार मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त(सीएमआरएस) की टीम ने डिपो और स्टेशनों का अवलोकन

किया। साथ ही ट्रेन का संचालन, स्पीड, इमरजेंसी ब्रेक सहित अन्य सुरक्षा मानकों की जांच की। सीएमआरएस की मंजूरी मिलते ही मेट्रो का कमर्शियल रन शुरू हो सकेगा। संभावना है कि इसी महीने या फरवरी से यात्री इसमें सफर कर सकेंगे। दो महीने से मेट्रो रेल कांफोरिशन दस्तावेजों पर काम कर रहा है। टीम के निरीक्षण का शेड्यूल नहीं मिलने से मेट्रो ने कमर्शियल रन की तारीखें भी बढ़ाई हैं। सीएमआरएस से ग्रीन सिग्नल मिलते ही इसी माह के अंत तक मेट्रो ट्रेन आमजन के लिए शुरू की जाएगी। शुरू में इसे निशुल्क होगी यात्रा जिस छह किलोमीटर हिस्से में मेट्रो चलाई जाना है वहां ज्यादा यात्री नहीं मिलेंगे। इसलिए शुरू में इसे निशुल्क चलाया जाएगा। मंगलवार को सीएमआरएस की टीम ने लोड

टेस्ट भी किया। अब तक ट्रेन के 11 सेट इंदौर को मिल चुके हैं। इन्हें 90 किमी प्रति घंटा की स्पीड पर चलाकर भी देखा गया। मेट्रो को गांधी नगर स्टेशन और सुपर कॉरिडोर के स्टेशन-3 के बीच 6 किमी ट्रैक पर चलाया जा रहा है। सितंबर 2023 में इस रूट पर मेट्रो का ट्रायल रन किया गया था। इस पूरे रूट पर पांच स्टेशन हैं, जिनका काम अब पूरा हुआ। टिकटिंग, एस्केलेटर, सीढ़ियां, लिफ्ट, वॉशरूम, कियोस्क, डिजिटल लॉकर, व्हीलचेयर, ऑटोमैटिक फ्लैप गेट, आरक्षित सीटें, आपातकालीन सुविधाएं आदि होंगी। इनमें से ज्यादातर की व्यवस्था हो चुकी है। कैफे, सोलर पैनल भी लगेंगे। मालूम हो, पहले चरण में 17.5 किमी के रूट पर मेट्रो का काम चल रहा है। इस पूरे रूट पर जुलाई तक कमर्शियल रन का दावा किया जा रहा है।

अभ्यर्थियों का आरोप- नेताओं के बच्चों को अधिक नंबर देकर डिप्टी कलेक्टर बनाया

सिटी चीफ इंदौर। इंदौर। एमपीपीएससी (मप्र लोक सेवा आयोग) की भर्तियों पर छात्र संगठन नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन (एनईवाययू) ने गंभीर आरोप लगाए हैं। संगठन ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारीयां पोस्ट की हैं और कहा है कि इंटरव्यू की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी इंटरव्यू की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। हाल ही में उन्होंने एक प्रेस वार्ता करके कहा है कि एमपीपीएससी के इंटरव्यू की रिकार्डिंग क्यों नहीं की जा रही है? मेन्स के परिणाम में थर्ड टापर रहे राम सोलंकी ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द साझा किया है। राम को मेन्स में 768 नंबर मिले और इंटरव्यू में उन्हें सिर्फ 75 नंबर दिए गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर कविता लिखकर कहा है कि मेन्स में सबसे ऊंचा था मेरा नाम, जब आया इंटरव्यू का पहल, सपनों पर लगा दिया भ्रष्टाचार का जहर। 75 अंक देकर किया किनारा, मेरी मेहनत को कर दिया बेसहारा। नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन (एनईवाययू) के सदस्यों का कहना है कि जिन छात्रों को मुख्य परीक्षा में सर्वाधिक नंबर आए वे इंटरव्यू में कम नंबर ला पाए और नेताओं के जो बच्चे मुख्य परीक्षा में कम नंबर लाए थे इंटरव्यू में उन्हें सर्वाधिक नंबर दिए गए। परिणाम यह हुआ कि मुख्य परीक्षा में सर्वाधिक अंक लाने वाले तहसीलदार बनकर रह गए और इंटरव्यू में मिले अधिक नंबरों के दम पर नेताओं के बच्चे डिप्टी कलेक्टर बन गए। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ छात्रों को लगातार हर परीक्षा में इंटरव्यू में बेहतर नंबर दिए गए। इंटरव्यू की रिकार्डिंग करवाने में क्यों डरता



है आयोग नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन (एनईवाययू) ने इस मुद्दे पर सवाल उठाए हैं और उनका कहना है कि इंटरव्यू को पारदर्शी तरीके से करने पर ही यह धांधली रुकेगी। संगठन के राधे जाट और रणजीत किसानवंशी ने कहा कि एक दो नहीं बल्कि इस तरह के सैंकड़ों मामले हैं जिनमें नेताओं के बच्चों और परिचितों को इंटरव्यू में अधिक नंबर देकर बड़े पदों पर बैठाया गया है। दोनों ने कहा कि इंटरव्यू की रिकार्डिंग करवाने और उसे जनता के बीच सार्वजनिक करने में आयोग क्यों डरता है। जब कोर्ट की रिकार्डिंग हो रही है तो आयोग के इंटरव्यू की रिकार्डिंग करने में क्यों रुकावट है। संगठन का यह भी कहना है कि इंटरव्यू का वेटेज कम करना चाहिए। इंटरव्यू के नंबर सिर्फ 100 ही रखना चाहिए ताकि इतना अधिक अंतर न आए।

प्रशासन को अपने हाथ में लेने की साजिश राधे और रणजीत ने कहा कि सरकार अपने परिचितों को प्रशासन में बड़े पदों पर बैठकर अगले कुछ साल में पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को अपने हाथों से नियंत्रित करना चाह रही है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो प्रशासन में सभी अधिकारी नेताओं के परिचित ही होंगे। एमपीपीएससी में मुख्य परीक्षा 1400 नंबर की होती है और 175 नंबर का इंटरव्यू होता है। संगठन का आरोप है कि नेताओं के जो बच्चे मुख्य परीक्षा में कम नंबर लाते हैं उन्हें इंटरव्यू में अधिक नंबर देकर बड़े पदों पर पहुंचा दिया जाता है। दोनों ने कहा कि पूरी सूची तैयार की जा रही है। इसमें कई नेताओं के परिचितों के नाम शामिल हैं। हम जल्द ही पूरी सूची सार्वजनिक करेंगे और सही फोरम पर मुद्दों को उठाएंगे।

महाकुंभ के लिए गई स्पेशल ट्रेन, साधु-संत और भक्तों के जत्थे हुए रवाना

सिटी चीफ इंदौर। इंदौर। इंदौर रेलवे स्टेशन से बुधवार दोपहर प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। ट्रेन खचाखच भरी हुई थी और जिनमें इस ट्रेन में सीट मिली, वे बेहद खुश नजर आ रहे थे। इस ट्रेन में साधु-संतों के अलावा भक्तों के जत्थे भी रवाना हुए। यह स्पेशल ट्रेन गुरुवार सुबह प्रयागराज पहुंचेगी। इसके अलावा 27 जनवरी को भी एक ट्रेन का संचालन महाकुंभ के मद्देनजर किया जाएगा। दोपहर में महु से ट्रेन 1.45 मिनट पर रवाना हुई। 2.10 बजे ट्रेन इंदौर पहुंची। यात्री इस ट्रेन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सफर में शामिल यात्री ढोलक, झांझ लेकर आए थे और स्टेशन पर भी भजन गाने लगे। 2.45 बजे ट्रेन इंदौर स्टेशन से रवाना हुई।



इस ट्रेन एक वार्ड से 200 यात्री आए थे, जबकि कई परिवारों ने ट्रेन की बुकिंग कर रखी थी। इस ट्रेन के कारण इंदौर रेलवे स्टेशन पर अम दिनों से ज्यादा भीड़ नजर आई। प्रयागराज जाने वाले यात्री दिल्ली होकर भी जा रहे हैं। इस कारण दिल्ली की ट्रेनों में भी रिजर्वेशन में मुश्किल हो रही है।

इंदौर से प्रयागराज तक प्लेन का सफर भी महंगा साबित हो रहा है। इंदौर से इसकी टिकट बीस से लेकर तीस हजार रुपये तक है। कई यात्री इंदौर से दिल्ली और टैक्सी या अन्य वाहनों से प्रयागराज जा रहे हैं। इंदौर में पांच दिन पहले टिकट 21 हजार रुपये था।

इंदौर में हुआ लाफिंग बुद्धा हैप्पीनेस सेशन का आयोजन



सिटी चीफ इंदौर। इंदौर। लाफिंग बुद्धा हैप्पीनेस सेशन का आयोजन ज्योतिर्मय योग केंद्र पर हुआ, इसमें आम जनता और अलग अलग व्यवसाय से जुड़े लोगों को तनाव से मुक्त होने के उपाय बताए गये, कार्यक्रम के मार्ग दर्शक लाफ्टर योगा कोच स्वामी उज्ज्वल जी थे और आयोजक श्री अनूप उपाध्याय, मनोज राजावत, डा ज्योति गोर,अवनीश त्रिपाठी,

मनीषा ठाकरे आदि थे। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का 3 बार प्रतिनिधित्व कर चुकी डा रोहिणी घावरी थी। इस कार्यक्रम में में सबसे पहले स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हैप्पीनेस सेशन किया गया जिसमें हेल्थ से संबंधित गतिविधियां जुंबा व एरोबिक्स के साथ, संगीत,गाने, डांस आदि मनोरंजन की गतिविधियां भी करायी गई,

साथ ही साथ जो भी सदस्य कार्यक्रम में आए थे उन सबको अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मौका दिया गया। उसके बाद एक जादू की झप्पी सेशन भी किया गया जिसमें आए हुए सभी सदस्यों को एक दूसरे से मिलने का मौका दिया गया जिसमें उन्होंने अपने परिचय के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, यह जानकारी कार्यक्रम की संयोजक मनीषा ठाकरे ने दी।

कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया बोले- भाजपा में गुटबाजी का कैंसर लाइलाज

सिटी चीफ इंदौर। इंदौर। महु में होने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के आयोजन की तैयारियों के सिलसिले में इंदौर आए प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष व विधायक विक्रांत भूरिया ने कहा कि महु में होने वाले कांग्रेस के आयोजन में दो लाख लोग एकत्र होंगे। आदिवासी परिवारों के साथ होने वाले अत्याचारों के खिलाफ यह आंदोलन सरकार की साथ हमारी लड़ाई को धार देगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी



के कांग्रेस में गुटबाजी के कैंसर के बयान पर विक्रांत ने कहा कि मैं डाक्टर हूँ, कैंसर का इलाज भी संभव है। स्टेज वन, स्टेज टू का इलाज होता है। कांग्रेस में छोटी मोटी गुटबाजी को खत्म किया जा रहा है। हम कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ हैं। कांग्रेस एकजुट है। भाजपा की गुटबाजी अनिर्यंत्रित हो गई है। इंदौर में दो पार्षदों की लड़ाई की चर्चा पूरे देश में है। मंत्री आपस में लड़ रहे हैं। भाजपा की गुटबाजी की स्थिति यह है कि इंदौर में भाजपा का शहर

अध्यक्ष नहीं बन पा रहा है। भाजपा में गुटबाजी का कैंसर लाइलाज है। अब भाजपा के खात्मे की शुरुआत हो चुकी है। मंत्री केलाश विजयवर्गीय के माफी मांगने के बयान पर उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब का अपमान संसद में किया है। फैशन बताकर उनका मजाक उड़ाया गया। क्या शाह महु आकर बाबा साहेब की प्रतिमा के सामने माफी मांगेंगे। भाजपा की सोच संविधान विरोधी है। बाबा साहेब को भाजपा ने पहले भी नहीं

अपनाया था और अभी भी भाजपा के नेता उनका अपमान करने से नहीं चुकते हैं। कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब का सम्मान किया है। जोबत क्षेत्र में ग्रेफाइट के ब्लॉक के केंद्र सरकार द्वारा लाइसेंस दिए जाने के सवाल पर भूरिया ने कहा कि पेसा कानून प्रदेश में लागू नहीं हुआ है। ग्राम सभा के बगैर ग्रेफाइट की खदानें दे दी गई हैं। इसमें कई आदिवासी परिवार प्रभावित हो रहे हैं। हम इसकी लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक लड़ेंगे।

सैफ अली खान से छिन जाएगा भोपाल नवाब का ताज?

सिटी चीफ भोपाल ।

भोपाल। एक्टर सैफ अली खान को भोपाल का नवाब कहा जाता है। भोपाल में उनकी अरबों की संपत्ति है और उनके परिवार का यहां राज हुआ करता था। अब उन्हीं संपत्तियों को लेकर विवाद है। अरबों की संपत्तियां शत्रु संपत्ति घोषित हो गई हैं। हालांकि इसमें अभी कई उलझन हैं। साथ ही पटींदी परिवार के पास अभी कई ऑप्शन भी बचे हैं, जिसकी वजह से लड़ाई और लंबी खींचेगी। लेकिन भोपाल की संपत्तियां अगर सरकार के पास चली जाती हैं तो सैफ अली खान से भोपाल नवाब का टैग छिन जाएगा। उनके पास जब संपत्तियां नहीं रहेगी तो वह



भोपाल के नवाब नहीं रहेंगे। वहीं, सरकार इस संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित कर अधिग्रहण करने की तैयारी में है। नवाब के टाइटल को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस विवाद की जड़ में 1949 में भोपाल रियासत का

भारत में विलय और 1947 का भोपाल गद्दी उत्तराधिकारी अधिनियम है। इस अधिनियम के तहत नवाब का टाइटल अभी भी कायम है। शत्रु संपत्ति कार्यालय ने आबिदा सुल्तान को नवाब का वारिस माना था। वहीं दूसरी ओर,

केंद्र सरकार ने साजिदा सुल्तान को उत्तराधिकारी घोषित किया था। इस विवाद से भोपाल की कई ऐतिहासिक संपत्तियों का भविष्य अधर में लटक गया है। लाखों लोगों के घरों पर भी इसका असर पड़ सकता है। **उलझ गया है मामला** भोपाल नवाब की प्रॉपर्टी को लेकर चल रहे विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। केंद्र सरकार के दो अलग-अलग आदेशों के चलते यह मामला और उलझ गया है। एक तरफ सरकार नवाब की 15 हजार करोड़ की संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित करके अपने कब्जे में लेने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ, नवाब के खिताब

को लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं है। इस पूरी उलझन की वजह केंद्र सरकार के दो आदेश हैं, जो एक-दूसरे से मेल नहीं खाते। **नवाब टाइटल अभी मान्य है** यह पूरा मामला 1949 में भोपाल रियासत के भारत में विलय से जुड़ा है। 1 जून 1949 को भोपाल रियासत का भारत संघ में विलय हो गया था। लेकिन 1947 के भोपाल गद्दी उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत नवाब का टाइटल अभी भी मान्य है। इस अधिनियम में साफ लिखा है कि नवाब हमीदुल्ला खान की सबसे बड़ी संतान ही भोपाल की नवाब होगी, चाहे वह बेटा हो या बेटी। मर्जर एग्रीमेंट के आर्टिकल 7 के

मुताबिक, भोपाल रियासत के उत्तराधिकारी को भारत सरकार मान्यता देगी। **आबिदा सुल्तान को माना है वारिस** इसी आधार पर शत्रु संपत्ति कार्यालय ने नवाब हमीदुल्ला खान की बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान को वारिस मानते हुए उन्हें भोपाल की नवाब माना था। इस हिसाब से अब यह टाइटल आबिदा के बेटे और पाकिस्तान के पूर्व विदेश सचिव शहररया खान की सबसे बड़ी संतान को मिलेगा। 24 फरवरी 2015 को शत्रु संपत्ति कार्यालय (मुंबई) ने भी एक सर्टिफिकेट जारी करके आबिदा को ही नवाब का वारिस

माना था। चूंकि आबिदा 1960 से पहले ही पाकिस्तान की नागरिक बन गई थीं, इसलिए 1960 तक नवाब की जो भी संपत्तियां थीं, वे शत्रु संपत्ति के दायरे में आ गईं। इन पर अब केंद्र सरकार का हक होगा।

1961 में साजिदा सुल्तान को वारिस घोषित किया वहीं, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1961 में भोपाल नवाब के निधन के बाद केंद्र सरकार ने उनकी छोटी बेटी साजिदा सुल्तान को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उनकी बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान पाकिस्तान की नागरिक बन चुकी थीं।

मोहन सरकार जनता के सुझाव से बना रही बजट

वित्त मंत्री आज विषय-विशेषज्ञों से करेंगे संवाद

सिटी चीफ भोपाल ।

भोपाल। मध्यप्रदेश की मोहन सरकार मार्च में राज्य का बजट पेश कर सकती है। इस बार सरकार को फोकस गरीब, युवा, महिला और किसान पर है। सरकार जनता से सुझाव लेकर अपना बजट तैयार कर रही है। 23 जनवरी को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट को लेकर विषय-विशेषज्ञों से संवाद करेंगे। मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार फरवरी अंत या मार्च के प्रथम सप्ताह में राज्य का बजट पेश कर सकती है। इस बार का बजट युवा, महिला, गरीब और किसान पर केंद्रित होगा। बजट में इन वर्गों के लिए चलाई जा रही योजनाओं में अधिक वित्तीय प्रावधान किया जाएगा। वित्त विभाग ने सभी विभागों के साथ बजट को लेकर बैठक कर ली है। मुख्यमंत्री सभी विभागों को युवा, महिला, गरीब और किसान वर्गों के लोगों को केंद्रीय योजनाओं का लाभ शत प्रतिशत उपलब्ध कराने के निर्देश दे चुके हैं।

‘बजट पर संवाद’आज

इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए बजट तैयारी के संबंध में ‘बजट पर संवाद’ 23 जनवरी को आर.सी.व्ही.पी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल में सुबह 10:30 बजे से होगा। बजट पर संवाद में उप मुख्यमंत्री एवं वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों के साथ चर्चा कर आगामी बजट को अधिकाधिक जनोपयोगी और प्रभावशाली बनाए जाने के लिए



बहुमूल्य सुझाव प्राप्त करेंगे। बता दें, इस बार का बजट 3 लाख 65 हजार करोड़ रुपये से अधिक का हो सकता है। हाल ही सरकार की 22 हजार करोड़ रुपए की राशि अलग-अलग विभागों को अनुपूरक बजट के माध्यम से उपलब्ध कराई। इसको मिलाकर बजट चार लाख करोड़ रुपये तक का हो सकता है।

क्षेत्र विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त करने हो रहा संवाद

वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने एवं भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाए जाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूर्ण करने में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में कृत संकल्पित है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए और आम जनता से जुड़ी हुई विभिन्न सुविधाओं को प्रदान करने के लिए उप मुख्यमंत्री के निर्देशन में वित्त विभाग बजट की तैयारी कर रहा है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों जैसे बैंकिंग, ग्रामीण-विकास, आर्थिक एवं वाणिज्यिक, जेंडर बजट,

पर्यावरण के विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त करने के लिए बजट पर संवाद किया जा रहा है। ह्यूबजट पर संवाद कार्यक्रम में बैंकिंग, अर्थशास्त्र, वित्त आयोग, उद्योग क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्यान, चिकित्सा, चार्टर्ड एकाडेंटेंसी, फिल्म में सफलता पूर्वक कार्य कर रहे हितधारकों को भी सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है।

जनता से मिले हजारों सुझाव

आम जनता से समाचार पत्रों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म , दूरभाष (0755-2700800), ई-मेल व पत्राचार के माध्यम से उनके सुझाव प्राप्त किए जा रहे हैं। इससे विकास की राह पर निरंतर आगे बढ़ रहे मध्य प्रदेश के आगामी बजट में अपने सुझावों के माध्यम से सहभागिता निभाकर प्रदेश की प्रगति और समृद्धि में आम जनता भी अपना योगदान दे सकेगी। अभी तक हजारों की संख्या में सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। यह मोहन यादव सरकार का दूसरा पूर्ण बजट होगा। ऐसे में वित्त विभाग के

अफसरों की मानें तो बजट सत्र फरवरी के आखिरी दिनों से शुरू होकर मार्च तक चलेगा। सत्र की अवधि करीब 20 दिनों की रखी जा सकती है। विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने के एक माह पहले राज्यपाल की अनुमति के बाद अधिसूचना जारी की जाएगी। इसमें विधायकों द्वारा किए जाने वाले ऑनलाइन और ऑफलाइन सवालों के साथ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा और अन्य सूचनाओं के बारे में समय तय किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जल्द ही बजट सत्र की पूर्ण रूपरेखा को अंजाम देंगे। इसके बाद राज्यपाल मंगू भाई पटेल की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि सत्र 27 फरवरी से 4 मार्च के बीच किसी भी तारीख से बुलाया जा सकता है। बता दें, कि मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट 3 जुलाई 2024 को प्रस्तुत किया था। यह वित्तीय वर्ष 2024–25 का बजट 3,65,067 करोड़ रुपये का था। जो कि वर्ष 2023–24 के मुकाबले 16 प्रतिशत अधिक था। इस बजट में सबसे ज्यादा बढ़त महिला एवं बाल विकास विभाग को दिया गया था। लाडली बहना योजना के लिए 18984 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया था। जबकि शिक्षा के लिए इस बजट में 22,600 करोड़ रुपए का प्रावधान था।

खंभे से टकराकर पलटी तेज रफ्तार कार, दो साढ़ु भाइयों की मौत

सिटी चीफ भोपाल ।

भोपाल। राजधानी के कोहेंफजा थाना क्षेत्र स्थित हलालपुरा बस स्टैंड के पास मंगलवार देर रात एक तेज रफ्तार कार बिजली के खंभे से टकराने के बाद पलट गई। इस हादसे में कार में सवार पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दो साढ़ू भाइयों की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल गर्भवती समेत तीन महिलाओं को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शवों का पीएम कराने के बाद लाश परिजन को सौंप दी। जानकारी के अनुसार महेंद्र सिंह मेवाड़ा पुत्र गुलाब सिंह मेवाड़ा (25) ग्राम मुंडला थाना रातीबड़ में रहता था और खेती किसानी करता था। उसका साढ़ू भाई सतीश मेवाड़ा पुत्र रमेशचंद्र मेवाड़ा (26) बिलकिसगंज, झगारिया जिले सीहोर का रहने वाला था। महेंद्र मेवाड़ा की पत्नी बबली बाई गर्भवती है। मंगलवार की रात उसे लेबर पेन शुरू हुआ तो महेंद्र

अपनी पत्नी बबली (22), मां बताशी बाई (55) और बुआ प्रेमबाई (60) के साथ पत्नी को हमीदिया अस्पताल लेकर पहुंचा। यहां ठीक से इलाज नहीं मिलने के बाद सभी लोग अल्टो कार से बैरागढ़ स्थित एक निजी अस्पताल जाने के लिए रवाना हुए। उस वक्त कार सतीश मेवाड़ा चला रहा था। रात करीब डेढ़ बजे सतीश की कार लालघाटी ओवर ब्रिज क्रॉस करने के बाद हलालपुरा बस स्टैंड के पास पहुंची, तभी अचानक कार अनियंत्रित होकर स्ट्रीट लाइट के लिए लगाए गए बिजली के खंभे से टकरा कर पलट गई। इस हादसे में कार में सवार सभी लोगों को गंभीर चोट आई थी। **बच्ची के जन्म से पहले पिता की मौत** हादसे के डेढ़ घंटे बाद गर्भवती महिला ने बच्ची को जन्म दिया। बच्ची के जन्म से पहले ही इस हादसे में उसके पिता और मौसा की मौत हो गई है। हादसा होते ही राहगीरों ने घायलों को कार से बाहर निकाला। सूचना मिलते ही

मौके पर पहुंची एंबुलेंस ने सभी को इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल पहुंचाया, जहां कुछ देर चले इलाज के बाद डॉक्टरों ने महेंद्र सिंह मेवाड़ा और सतीश मेवाड़ा को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल से मिली सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शवों को पीएम के लिए भेज दिया और बुधवार को पोस्टमॉर्टम के बाद लाश घरवालों को सौंप दी गई। घायल हुई तीनों महिलाओं का इलाज चल रहा है। तेज रफ्तार बनी हादसे का कारण घटना के समय परिवार का एक अन्य रिश्तेदार अशोक मेवाड़ा आटो में बैठकर कार से पीछे चल रहा था। उसने पुलिस को बताया कि बबली को काफी ज्यादा प्रसव पीड़ा हो रही थी, इसलिए अस्पताल जल्दी पहुंचना था। इसी जल्दबाजी के कारण सतीश काफी तेज रफ्तार से कार चला रहा था। अनुमान है कि रफ्तार ज्यादा होने के कारण कार अनियंत्रित होकर खंभे से टकरा गई होगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बीएमएचआरसी के यूरोलॉजी विभाग में शुरू होगा एमसीएच कोर्स

सिटी चीफ भोपाल ।

भोपाल स्मारक अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र (बीएमएचआरसी) के एक और विभाग में सुपर स्पेशियलिटी कोर्स शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। संस्थान को एनएमसी (नैशनल मेडिकल काउंसिल) से यूरोलॉजी विभाग में एमसीएच कोर्स शुरू की अनुमति प्राप्त हो गई है। यूरोलॉजी में एमसीएच की दो सीटें होंगी। काउंसिलिंग के बाद विभाग में नए स्ट्रुडेंट्स आ जाएंगे। बीएमएचआरसी की

प्रभारी निदेशक डॉ मनीषा श्रीवास्तव ने यूरोलॉजी विभाग में एमसीएच कोर्स शुरू होने की अनुमति मिलने पर खुशी जताई है। उन्होंने बताया कि विभाग में एमसीएच स्ट्रुडेंट्स आ जाने से मरीजों को और बेहतर उपचार प्राप्त होगा तथा विभाग की कार्यक्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि बीएमएचआरसी को पूरी तरह पीजी इंस्टिट्यूट बनाने की कोशिश की जा रही है। कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, एनेस्थीशियोलॉजी, मनोचिकित्सा,

माइक्रोबायोलॉजी विभाग, कार्डियक थोरोसिक एवं वस्कुलर सर्जरी विभाग और ऑर्थेलमोलॉजी विभाग में पीजी या सुपरस्पेशियलिटी कोर्स पहले से ही संचालित हैं। पैथोलॉजी और टॉसफ्यूजन विभाग में भी अगले वर्ष पीजी कोर्स शुरू होने की उम्मीद है। डॉ श्रीवास्तव ने बताया कि हाल ही में यूरोलॉजी विभाग में दो यूरोलॉजिस्ट ने जॉइन किया है। इस तरह अब विभाग में तीन कन्सल्टेंट हो गए हैं।

चोरी करने घुसे बदमाशों को भीड़ ने जमकर पीटा, किया पुलिस के हवाले

सिटी चीफ भोपाल ।

भोपाल। भोपाल के कमला नगर थाना इलाके में स्थित राहुल नगर में दो चोर एक महिला के घर में दाखिल हो गए। देर रात चोरों को घर में घुसा देख महिला ने शोर मचा दिया। तभी आरोपियों ने सभी महिला को गेंती का दस्ता फेंककर मारा और भागने का प्रयास किया। हालांकि, लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और जमकर पीटा। घटनाक्रम का

वीडियो भी सामने आया है। दोनों आरोपियों को रहवासियों ने पुलिस के हवाले कर दिया। जामनी बाई (35) राहुल नगर झुग्गी में रहती हैं और गृहिणी हैं। मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे उन्हें घर में किसी के होने की आहट हुई। उठकर देखा तो दो युवक खड़े थे। महिला ने शोर मचाया तो आरोपी में से एक ने महिला को पास में रखी गेंती का दस्ता फेंककर मारा। इससे

महिला के हाथ में चोट आई है। हालांकि महिला की शोर की आवाजें सुनकर आसपड़ोस के लोगों की नींद खुल गई। इसी दौरान भागने का प्रयास कर रहे युवकों को भीड़ ने जमकर पीट दिया। आरोपियों की पहचान ऋषि मालवीय और पवन अंबारे के रूप में हुई है। दोनों हबीबगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। भीड़ ने दोनों युवकों को जमकर पीटा। जिसका वीडियो भी सामने

आया है। हालांकि, वीडियो में कुछ लोग दोनों युवकों को बचाते हुए भी दिखाई दिए हैं। कमला नगर पुलिस ने दोनों के खिलाफ चोरी के प्रयास का केस दर्ज कर लिया है। सीपी चंद्र शेखर पांडे के मुताबिक आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। दोनों चोरी के इरादे से महिला के घर में दाखिल हुए। उनके पुराने अपराधों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।

जीतू पटवारी को समय नहीं दे रहे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज

भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी 19 मंगलवार से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने का समय मांग रहे हैं। लेकिन अभी तक उनके द्वारा मिलने का समय नहीं दिया गया। जिसके चलते कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने शिवराज सिंह को उनका वादा याद दिलाते हुए निशाना साधा है। जिसमें उन्होंने कहा कि अठारह मंगलवार बीत गए और उन्नीसवां आ गया लेकिन इंतजार है कि जो खत्म ही नहीं हो रहा कांग्रेस

अध्यक्ष पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज उन्नीसवां मंगलवार आ गया, लेकिन आपकी ओर से अब तक कोई जवाब नहीं आया। आपने वादा किया था कि हर मंगलवार किसानों से मिलेंगे। मध्य प्रदेश का किसान होने के नाते, मैं एक बार फिर प्रदेश के किसानों के साथ इस मंगलवार भी आपसे मिलने का निवेदन कर रहा हूं। पिछले छह महीनों से मैं प्रदेश के कोने-कोने में जाकर किसानों से मिल रहा हूं। हर

जगह किसान अपनी फसल के दाम न मिलने, मुआवजे की अनदेखी और सरकारी उदासीनता से परेशान हैं। आपके अपने ही गृह राज्य के किसानों को आखिर कब तक आपसे समय मांगना पड़ेगा? जानकारी के लिए बता दें कि इस साल की शुरुआत में एक जनवरी को जीतू पटवारी ने कहा था कि वे 100 मंगलवार तक शिवराज सिंह चौहान के बुलावे का इंतजार करेंगे, और फिर उसके बाद खुद जाकर उनसे मुलाकात करेंगे।

विधायक प्रीतम लोधी ने बनाए 20 प्रतिनिधि, अब खुद किसी मीटिंग में नहीं जाएंगे

सिटी चीफ भोपाल ।

भोपाल। सांसद और विधायक द्वारा प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते हैं, ऐसा करने की परंपरा पुरानी है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि नेता अपना काम आसानी से कर सकें। लेकिन, प्रदेश के एक विधायक ने अलग-अलग विभागों के अलग-अलग प्रतिनिधि नियुक्त करने की नई परंपरा शुरू कर दी है। उन्होंने पुलिस थाने से जुड़े कामों के लिए भी एक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया है। इस प्रतिनिधि को थाने से संबंधित सभी कामों से लेकर यहां होने वाली बैठकों में विधायक का प्रतिनिधित्व करने के विधिवत आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल, मामला शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा का है। यहां के विधायक प्रीतम लोधी ने यह फरमान जारी किया है। उन्होंने जिला कलेक्टर को इस बाबत सूचित भी किया है। उन्होंने क्षेत्रीय



भाजपा नेता इंदल लोधी कुंदोली को विधायक प्रतिनिधि घोषित किया है। साथ ही पुलिस विभाग से संबंधित सभी काम करने के लिए उन्हें अधिकृत किया है। जारी पत्र में विधायक लोधी ने इंदल लोधी को पुलिस विभाग से संबंधित सभी बैठकों आदि के लिए भी अधिकृत किया है। **कोई शासकीय प्रावधान नहीं** आमतौर पर सांसद और विधायक द्वारा अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते हैं। इनके जिम्मे जिला प्रशासन की विभिन्न बैठकों में शामिल होने का प्रावधान होता है। यह प्रतिनिधि इन बैठकों में शामिल होकर अपने नेता की बात रखने या जानकारी देने के लिए अधिकृत होते हैं। इसके लिए कोई शासकीय प्रावधान नहीं होता है। लेकिन, पुलिस विभाग में अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किए जाने का यह संभवतः पहला

मामला है। **हर विभाग का एक प्रतिनिधि होगा** विधायक प्रीतम लोधी ने इस नियुक्ति को अपने नवाचार से जोड़ा है। उनका कहना है कि वे शासन के सभी विभागों का एक अलग प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे। इस कड़ी में वे करीब 20 विभागों के यह प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। बाकी विभागों के लिए भी वे काम कर रहे हैं। विधायक लोधी का कहना है कि उन्होंने जनता और अपने कार्यकर्ताओं से वादा किया है कि वे कभी अपनी कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, बल्कि उनके कार्यकर्ता और प्रतिनिधि ही विधायक की भूमिका निभाएं। उनका कहना है कि जनता के काम आसानी से हों और उन्हें अपनी किसी समस्या के लिए विधायक पर निर्भर न रहना पड़े, इसी मंशा के साथ अलग-अलग विभागों के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किए जा रहे हैं।

सम्पादकीय

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के तेवर और भारत की चिंताएं

ट्रंप के पहले कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच संबंध मजबूत हुए थे। रक्षा से लेकर व्यापार तक, भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच संबंध विकसित हुए हैं। लेकिन ट्रंप के कदमों को लेकर भारत के लिए तीन मुख्य चिंताएं हैं। पहला, द्विपक्षीय व्यापार के लिए उनका दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होगा, और यहीं से ध्यान केंद्रित करना शुरू होगा। हमें यह देखना होगा कि यह कैसे सामने आता है। दूसरा, हिंद-प्रशांत रणनीति ट्रंप के नेतृत्व में गठबंधनों के भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। तीसरा, हिंद-प्रशांत की क्षेत्रीय रणनीति पर विचार करना सिर्फ एक पहलू है; अपने सहयोगियों के साथ ट्रंप की कार्रवाइयां इस बात को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेंगी कि भारत को विभिन्न चुनौतियों के लिए कैसे अनुकूल होना चाहिए।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पदभार संभालने के साथ ही आने वाले दिनों और हफ्तों में उनके कार्यों और निर्णयों पर दुनियाभर की कड़ी नजर होगी। व्हाइट हाउस में ट्रंप की वापसी से भारत और अमेरिका के बीच संबंधों के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले, ट्रंप 2017 से 2020 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे और इस अवधि में ऐसे बड़े निर्णय लिए गए, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को नया आकार दिया। पिछले कार्यकाल में ट्रंप के बड़े फैसलों में पेरिस जलवायु समझौते और ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका को अलग करना, उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन के साथ ऐतिहासिक बैठक और पश्चिम एशिया में अब्राहम समझौते की स्थापना शामिल है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच संबंध मजबूत हुए थे। रक्षा से लेकर व्यापार तक, भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच संबंध विकसित हुए हैं। लेकिन ट्रंप के कदमों को लेकर भारत के लिए तीन मुख्य चिंताएं हैं। पहला, द्विपक्षीय व्यापार के लिए उनका दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होगा, और यहीं से ध्यान केंद्रित करना शुरू होगा। हमें यह देखना होगा कि यह कैसे सामने आता है। दूसरा, हिंद-प्रशांत रणनीति ट्रंप के नेतृत्व में गठबंधनों के भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। तीसरा, हिंद-प्रशांत की क्षेत्रीय रणनीति पर विचार करना सिर्फ एक पहलू है; अपने सहयोगियों के साथ ट्रंप की कार्रवाइयां इस बात को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेंगी कि भारत को विभिन्न चुनौतियों के लिए कैसे अनुकूल होना चाहिए। उदाहरण के लिए, जापान के साथ उनके व्यवहार का हिंद-प्रशांत क्षेत्र में जापानी रणनीति पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है, जिसका असर भारत पर भी पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए जोश के साथ अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत कर दी है। अपने शपथ ग्रहण अभिभाषण में उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब अमेरिका स्वर्णकाल में वापसी करने जा रहा है। हालांकि वे चुनाव प्रचार के दौरान भी बार-बार दोहराते रहे कि सत्ता में आने के बाद वे ‘अमेरिका प्रथम’ की नीति पर काम करेंगे। सत्ता की कमान संभालते ही उन्होंने इस पर अमल भी शुरू कर दिया। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद उन्होंने घुसपैठ रोकने के लिए सीमा पर आपातकाल लगा दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका को अलग कर दिया। पेरिस जलवायु समझौते को अमान्य कर दिया। ब्रिक्स देशों को चेताया है कि अगर उनमें से कोई भी अमेरिकी नीतियों के विरुद्ध चलने का प्रयास करेगा, तो उसे उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। वे आब्रजन संबंधी नियम-कायदों को वे सख्त बनाना चाहते हैं। अमेरिका में निर्यात करने वाले कई देशों पर उन्होंने भारी शुल्क की घोषणा कर दी है और अन्य देशों पर भी वे ऐसा ही कदम उठाने वाले हैं। उन्होंने धड़ाधड़ प्रशासनिक फेरबदल शुरू कर दिए हैं। इस तरह दुनिया के तमाम देशों की नजर इस बात पर टिकी है कि ट्रंप प्रशासन उनके साथ कैसा व्यवहार करता है। डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में ही अमेरिका केंद्रित नीतियों के पक्षधर थे। उस दौरान उन्होंने वाणिज्य-व्यापार और आब्रजन संबंधी नीतियों को सख्त बनाने के प्रयास किए थे। हालांकि दबाव में आकर उन्हें अच-वन बी वीजा पर रोक संबंधी फैसले को वापस लेना पड़ा था। इस बार भी कार्यभार संभालने से पहले ही इस वीजा को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी, मगर एलन मस्क के दबाव में उन्होंने इसे ज्यादा तूल नहीं दिया। हालांकि वे घोषणा कर चुके हैं कि आब्रजन और नागरिकता नियमों को सख्त बनाया जाएगा। जाहिर है, इससे बहुत सारे लोगों को अमेरिका छोड़कर अपने देश लौटना पड़ेगा। इसकी आशंका वहां बसे भारतीय मूल के लोगों को अधिक सता रही है। हालांकि ट्रंप ने अभी तक भारत को लेकर कोई कठोर कदम उठाने की बात नहीं कही है। अब तक भारत के साथ अमेरिका के संबंध मधुर रहे हैं। वाणिज्य-व्यापार में संतुलन बना रहा है। कूटनीतिक संबंधों में वैसी तलखी कभी नहीं देखी गई, जैसी चीन के साथ रहती है। मगर ट्रंप ने जिस आक्रामक ढंग से कामकाज शुरू किया है और जैसे फैसले करने को कहते आ रहे हैं, उसमें कुछ आशंकाएं स्वाभाविक हैं। छिपी बात नहीं है कि अमेरिका की प्रतिस्पर्धा चीन से है।

युद्धमुक्त विश्व के ट्रंप के संकल्पों की रोशनी

राष्ट्रपति के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल पर लौटने से पहले ट्रंप ने ‘तीसरा विश्व युद्ध’ रोकने की कसम खाकर दुनिया में शांति, अमन एवं अयुद्ध की संभावनाओं को बल दिया है। 47वें राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप ने शपथ से एक दिन पहले गाजा में हुए युद्ध विराम का क्रेडिट भी लिया। रूस और यूक्रेन युद्ध भी खत्म करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है।

बावजूद इनके विश्व युद्ध के कयास तेजी से लग रहे हैं। इसे लेकर भी कई सवाल उठते हैं कि क्या सच में तीसरा विश्व युद्ध होना इतना आसान है? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ‘मैं यूक्रेन में युद्ध खत्म कर दूंगा। मैं मध्य पूर्व में अराजकता रोक दूंगा और मैं तीसरे विश्व युद्ध को होने से रोक दूंगा।’ निश्चित ही ट्रंप के इन संकल्पों से अमेरिका में एक नए युग का आगाज हो रहा है।

राष्ट्रपति के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल पर लौटने से पहले ट्रंप ने ‘तीसरा विश्व युद्ध’ रोकने की कसम खाकर दुनिया में शांति, अमन एवं अयुद्ध की संभावनाओं को बल दिया है। 47वें राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप ने शपथ से एक दिन पहले गाजा में हुए युद्ध विराम का क्रेडिट भी लिया। रूस और यूक्रेन युद्ध भी खत्म करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। बावजूद इनके विश्व युद्ध के कयास तेजी से लग रहे हैं। इसे लेकर भी कई सवाल उठते हैं कि क्या सच में तीसरा विश्व युद्ध होना इतना आसान है? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ‘मैं यूक्रेन में युद्ध खत्म कर दूंगा। मैं मध्य पूर्व में अराजकता रोक दूंगा और मैं तीसरे विश्व युद्ध को होने से रोक दूंगा।’ निश्चित ही ट्रंप के इन संकल्पों से अमेरिका में एक नए युग का आगाज हो रहा है, जो दुनिया में भी एक नई युद्ध मुक्त समाज-संरचना के बड़े बदलावों की ओर इशारा कर रहा है। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से ही ट्रंप कई संकेत ऐसे दे चुके हैं, जिनसे लगने लगा है कि दुनिया बदलने वाली है। ये बदलाव इस बात पर केंद्रित रहेंगे कि अमेरिका को फिर एक बार महान बनना है। यह ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’का नारा डोनाल्ड ट्रंप की एक नई पहचान बन गया है और बहुत संभावना है कि इस बार ट्रंप अपने सपने को साकार करने के लिए दुस्साहस का भी परिचय देते हुए युद्ध की मानसिकता वाले देशों की सोच में बदलाव का कारण बन जाए।



विश्व में अनेक देशों के बीच युद्ध चल रहे हैं एवं ऐसे ही युद्ध की व्यापक आशंकाएं बनी हुई हैं। विश्व युद्ध कई कारणों से शुरू हो सकते हैं। जैसे राष्ट्रवाद यानी अपने देश के प्रति अत्यधिक लगाव और अन्य देशों के प्रति घृणा। जब राष्ट्रवाद चरम पर पहुंच जाता है तो युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है या फिर एक शक्तिशाली देश दूसरे देशों पर अपना अधिकार जमाना चाहता है, तो इससे युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। इसके अलावा देशों के बीच आर्थिक प्रतिस्पर्धा भी युद्ध का कारण बन सकती है। साथ ही धार्मिक मतभेद भी युद्ध का कारण बन सकते हैं और किसी देश में राजनीतिक अस्थिरता होने पर पड़ोसी देशों में भी अशांति फैल सकती है और युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। युद्ध की इन व्यापक संभावनाओं पर ट्रंप के संकल्प से विराम लगना विश्व की समाज-व्यवस्था, आर्थिक विकास एवं सह-जीवन के लिये एक शुभ संकेत है। क्योंकि विश्व युद्ध के परिणाम बहुत ही विनाशकारी होते हैं। इसमें लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। युद्ध से देशों की अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंचता है। साथ ही युद्ध से समाज में अस्थिरता फैल जाती है, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी बढ़ जाती है और युद्ध के बाद देशों के राजनीतिक नक्शे में बदलाव आ सकता है।

अमेरिका दुनिया में अमन चाहता है और नए राष्ट्रपति ट्रंप ने यदि किसी भी देश के युद्ध में सेना नहीं भेजने का संकल्प लिया है तो इससे दुनिया में युद्ध की संभावनाओं पर विराम लगना तय है। क्योंकि अब तक शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका ही दुनिया मे युद्ध की भूमि तैयार करता रहा है, अपनी सेना एवं सैन्य सामान भेज कर युद्ध की भूमि को उर्वरा बनाता रहा है। विश्व समुदाय कई संकटों का सामना कर रहा है- संघर्ष और हिंसा, आतंक एवं अलगाव, युद्ध एवं राजनीतिक वर्चस्व, गरीबी एवं बेरोजगारी, लगातार सामाजिक-आर्थिक असमानताएं, पर्यावरणीय संकट और दुनियाभर के लोगों के स्वास्थ्य और भलाई के लिए चुनौतियां आदि जटिलतर स्थितियों के बीच ट्रंप के नए संकल्प एवं योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हो

सकती है। आज युद्ध और तनाव की समस्या बढ़ती जा रही है। हथियारों का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। हर देश परमाणुशक्ति संपन्न बनने के लिए प्रयासरत है। यह एक अजीबोगरीब स्थिति है। युद्ध की आशंका को खत्म करने के लिए हाथियारों का जखीरा बढ़ाया जा रहा है। पहले बीमारी पैदा की जा रही है, फिर उसके इलाज का उपाय ढूंढा जा रहा है। इसमें अब तक अमेरिका की ही सर्वाधिक भूमिका रही है, लेकिन अब उसके नये राष्ट्रपति की युद्धमुक्त विश्व संरचना की सोच से दुनिया में शांति एवं अमन कायम होगा। युद्ध से कभी किसी का भला नहीं होता। वह सदैव अपने पीछे दुख भरी यादें छोड़कर जाता है। युद्ध से किसी मां का बेटा उसे बिछड़ जाता है, किसी बहन का भाई उससे बिछड़ जाता है, कोई स्त्री अपने पति को खो देती है, कोई बेटी अपने पिता को खो देती है। इस तरह युद्ध केवल जान लेता है। इसके अलावा युद्ध से संपत्ति भी नष्ट होती है एवं विकास अवरूद्ध होता है। इसके विपरीत यदि सब जगह शांति हो, लोग आपस में नहीं लड़ें, देशों में आपस में युद्ध नहीं हो, तो विकास होता है।

ट्रंप ने अमेरिकी राजनीति के तेवर-कलेवर को तो बदला ही है और वह वहां लोकतंत्र को भी बदलने जा रहे हों, तो कोई आश्चर्य नहीं। उनकी टीम के अनेक दिग्गज परिवर्तन के आकांक्षी हैं। न जाने कितने परिवर्तन ट्रंप के शासन में लागू होंगे। उम्मीद करनी चाहिए कि ट्रंप की नई टीम अमेरिकी परंपराओं का यथासंभव निर्वाह करते हुए ही देश को फिर से महान बनाएगी। लेकिन इस बार अमेरिकी परम्पराओं में युद्ध एवं हिंसा के स्थान पर शांति, विकास एवं हथियार मुक्ति के संकल्प होना बड़ी एवं राहतभरी बात है। हालांकि, अमेरिका को महान बनाने के अभियान पर कई सवाल भी हैं। क्या अमेरिकी निर्णायकों ने मान लिया है कि अमेरिका अब महान नहीं रहा? इस अभियान के नाम से तो शायद यही लगता है कि अमेरिकी विचारकों ने अपने देश के महान न रह पाने की वजहों का पता भी लगा लिया है। उनकी नजर उन अमेरिकी चालाकियों पर भी निस्संदेह पड़ी होगी, जिनकी वजह से

अमेरिकियों की अक्सर आलोचना होती है। इन वजहों में युद्ध एवं हथियारों की होड़ बड़ी वजह रही है। अनेक राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि युद्ध, हिंसा, आतंकमुक्त नये अमेरिका को विकसित करने एवं विश्व में शांति के संकल्प को देखते हुए अमेरिका को शुरू से ही भारत के साथ खड़ा रहना चाहिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका सबसे पुराना जीवित लोकतंत्र है, दुनिया में युद्ध एवं आतंक के खिलाफ भारत हमेशा अग्रसर रहा है, युद्ध का अंधेरा मिटाने, शांति का उजला करने एवं अहिंसा-सहजीवन की कामना ही भारत का लक्ष्य रहा है। इसीलिये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार युद्ध विराम की कोशिश करते रहे हैं।

ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों पर क्या असर होगा, इसे लेकर विशेषज्ञ कई तरह की उम्मीदें जता रहे। जानकारों के मुताबिक, ट्रंप के आने से भारत और अमेरिका के संबंध और गहरे होंगे। चीन को लेकर दोनों देशों की चिंता इन्हें करीब लाएगी। यह ट्रेंड पिछले पांच अमेरिकी राष्ट्रपतियों के कार्यकाल जैसा ही रहेगा। क्राड और मजबूत होगा। प्रशासन के कई विभागों में भारत के अच्छे संबंध बनेंगे। राजनीतिक और वैचारिक तालमेल भी अच्छा रहने की उम्मीद की जा रही। इसके साथ ही रक्षा, खुफिया और सुरक्षा मामलों में दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी में सहयोग की संभावनाएं बढ़ने के आसार हैं। सबसे अहम है भारत की युद्ध एवं आतंक मुक्त विश्व बनाने की योजना, इसको लेकर ट्रंप भी आगे आये है जो नये सूरज का अभ्युदय है। लेकिन ट्रंप का नया दौर कहीं मौखिक हमलों या कटु उद्गारों तक ही सीमित न रह जाए। इसके लिये जरूरी है कि वह भारत की शांतिपूर्ण नीतियों एवं योजनाओं का अग्रसर करें। भारत सहित तमाम दुनिया यही उम्मीद करेगी कि ट्रंप दुनिया में चल रहे बड़े युद्धों और छद्म युद्धों को रोकने में सफलता हासिल करें साथ ही आतंकवाद के खिलाफ ईमानदार रवैया अपनाने ताकि नई उबरती उभरती दुनिया में अमेरिकी सचमुच महानता का वरन कर सके।

जलगांव रेल हादसा: क्या कोई सबक लेगा ? अफवाहें और घबराहट से बचाने की जिम्मेदारी किसकी?

महाराष्ट्र के जलगांव जिले में पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह ने 12 निर्दोष यात्रियों की जान ले ली। अफवाह सुनते ही यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। किसी ने चेन पुलिंग की, तो कुछ यात्री चलती ट्रेन से कूद गए। घबराहट में कई यात्री पास की पटरियों पर बैठ गए, और दुर्भाग्यवश विपरीत दिशा से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस ने उन्हें कुचल दिया। यह हादसा भारतीय रेलवे की व्यवस्था और यात्रियों की सुरक्षा के प्रति हमारी लापरवाही को उजागर करता है।

21 जनवरी 2025 की सुबह, लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस के एक कोच में चिंगारी उठने की घटना ने भयानक मोड़ ले लिया। इस छोटी-सी घटना को कुछ यात्रियों ने आग लगने की अफवाह में बदल दिया। भयभीत यात्रियों ने हड़बड़ी में ट्रेन रुकवाई और कुछ ने बिना सोचे-समझे छल्लांग लगा दी। इसी बीच, कर्नाटक एक्सप्रेस विपरीत दिशा से आ रही थी, और पास की पटरी पर बैठे लोग उसकी चपेट में आ गए। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। एक प्रत्यक्षदर्शी यात्री ने बताया कि जब यात्री ट्रेक पर थे तो आने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस ने अपना हॉर्न भी नहीं बजाया। उन्होंने कहा, अगर कर्नाटक एक्सप्रेस ने हॉर्न बजाया होता तो यात्री सतर्क हो जाते रेलवे प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया, लेकिन यह जान बचाने के लिए काफी देर हो चुकी थी। रेलवे एक ऐसी व्यवस्था है, जहां हर छोटी-सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। जलगांव हादसे ने रेलवे और प्रशासन की कई खामियों को उजागर किया है।

1. सुरक्षा प्रोटोकॉल का अभाव-ट्रेन के भीतर यात्री और स्टाफ के बीच संचार की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। अगर तत्काल स्थिति



स्पष्ट की जाती, तो शायद घबराहट टाली जा सकती थी। 2.यात्रियों की जागरूकता- भारतीय रेलवे में सुरक्षा संबंधी जागरूकता का घोर अभाव है। यात्रियों को यह समझना चाहिए कि घबराहट और अफवाहें जानलेवा हो सकती हैं।इस घटना में भी कर्नाटक एक्सप्रेस के ड्राइवर को हार्न बजाकर लोगों को सचेत करना चाहिए था। 3.रेलवे स्टाफ की जवाबदेही- ट्रेन टिकट निरीक्षक (टीटीई) और अन्य कर्मचारियों को ऐसी आपातकालीन परिस्थितियों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। ऐसी घटनाओं से बचने के लिये बोगियों में इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए । प्रत्येक कोच में लाउडस्पीकर या डिस्टले स्क्रीन होनी चाहिए, जहां ड्राइवर, गार्ड या टीटीई तत्काल घोषणाएं कर सकें।कोचों में आपातकालीन इंटरकॉम सिस्टम लगाया जाना चाहिए, ताकि यात्रियों की संदेहपूर्ण स्थिति में सीधे ट्रेन स्टाफ से संवाद हो सके। साथ ही यात्रियों को जागरूक करना भी बहुत आवश्यक है । हवाई जहाज की तरह ट्रेन में यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान सुरक्षा

दिशानिर्देश दिए जा सकते हैं। विशेषकर लंबी दूरी की ट्रेनों में सुरक्षा उपायों की जानकारी देना अनिवार्य किया जाना बेहतर होगा। इसके अलावा टीटीई और स्टाफ की जवाबदेही निर्धारित की जानी चाहिए। टीटीई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी आपात स्थिति में यात्रियों को पैनिक न होने दिया जाए।इसके लिये सभी ट्रेन स्टाफ को नियमित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे आपातकालीन परिस्थितियों में शांत और व्यवस्थित तरीके से स्थिति को संभाल सकें। ट्रेनों में अफवाहों पर सख्त कदम उठाने बहुत जरूरी हैं । ट्रेन में किसी भी प्रकार की झूठी सूचना फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिये । रेलवे को साइबर सुरक्षात्मक तंत्र भी विकसित करना चाहिए, जिससे सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों पर फैलने वाली झूठी सूचनाओं पर तत्काल रोक लगाई जा सके। भारतीय रेलवे में ऐसी घटनाएं नई नहीं हैं। 2012 में भी एक एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने की अफवाह ने कई यात्रियों की जान ली थी। हर बार ऐसी घटनाओं से सबक लेने की बात की जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर ठोस कदम उठाए बिना यह समस्या बनी रहती है। जलगांव का यह हादसा हमारी असावधानी और घबराहट के गंभीर परिणामों का प्रतीक है। यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि हमें अपनी व्यवस्थाओं को सुधारने और यात्रियों को जागरूक बनाने की आवश्यकता है। रेलवे प्रशासन, यात्रियों और सरकार के बीच बेहतर समन्वय ही इस तरह की त्रासदियों को रोक सकता है। हमें इस घटना से सबक लेते हुए अपनी कमजोरियों को सुधारने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। (राजीव खरे ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़)

आरजी कर कांड में अदालती फैसले के बाद भी अनसुलझे सवाल

कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ रेप के बाद उसकी हत्या के मामले में कोलकाता की एक अदालत ने इस मामले के इकलौते अभियुक्त संजय राय को आजीवन कारावास की सजा तो सुना दी है। लेकिन इस घटना से संबंधित कई सवालों के जवाब अब भी अधर में हैं। दूसरी ओर अभियुक्त के वकील ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। सीबीआई की दलीलों के बावजूद जज ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला नहीं माना। दूसरी ओर, पीड़िता के माता-पिता के अलावा इस घटना के विरोध में महीनों से आंदोलन करने वाले जूनियर डॉक्टरों और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक ने अभियुक्त को फांसी की सजा नहीं मिलने पर असंतोष जताया है। पीड़िता के पिता का कहना था कि सीबीआई इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला साबित करने में नाकाम रही है। अगर वैसा होता तो अभियुक्त को फांसी की सजा मिलती। उनका कहना था कि इस मामले में अभी कई अन्य लोग भी शामिल हैं। उन सबको कटघरे में लाना चाहिए। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जूनियर डॉक्टरों के संगठन वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने भी यही बात कही है। उधर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि हमने दोषी के लिए फांसी की मांग उठाई थी। अगर यह मामला कोलकाता पुलिस के हाथों में होता तो दोषी को फांसी की सजा ही मिलती। बीते साल नौ अगस्त को आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर का शव बरामद किया गया था। उसके साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी के फुटेज और दूसरे सबूतों के आधार पर इस मामले में कोलकाता के पुलिस के सिविक वालंटियर संजय को गिरफ्तार किया था। 13 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। इस घटना ने लंबे समय तक देश-विदेश में सुर्खियां बटोरी थी। दूसरी ओर,

इस घटना के विरोध में राज्य के तमाम जूनियर डॉक्टरों ने लंबे समय तक धरना-प्रदर्शन और आमरण अनशन किया था। अदालत में पीड़िता के माता-पिता के अलावा सीबीआई ने इसे ‘रेयरेस्ट ऑफ द रेयर’ मामला बताते हुए अभियुक्त के लिए मौत की सजा की मांग की थी। लेकिन बचाव पक्ष के वकील ने अदालत से संजय को सुधरने का एक मौका देने की अपील करते हुए कहा था कि उसको मौत की सजा नहीं दी जाए। इस मामले की सुनवाई बीते 11 नवंबर को शुरू हुई थी। यानी नौ महीने बाद फैसला आया है, लेकिन अब भी इससे जुड़े कई सवालों के जवाब अंधेरे में हैं। वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स फ्रंट से जुड़े डॉ. किंजल नंद बताते हैं कि शुरू से ही इस मामले की जांच में भारी लापरवाही बरती गई और कई अहम सबूतों को या नष्ट होने दिया गया या फिर उसे नष्ट करने वालों से ठीक से पूछताछ नहीं की गई। उनका सवाल था कि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और स्थानीय थाने के ऑफिसर इंचांज अभिजीत मंडल को सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन सीबीआई तय समय सीमा में उनके खिलाफ आरोपपत्र दायर नहीं कर सकी। नतीजतन उनको जमानत मिल गई। आखिर सीबीआई ने ऐसा क्यों किया? उनका सवाल है कि पीड़िता का शव सुबह बरामद होने के बाद उसका पोस्टमार्टम शाम को किया गया और प्राथमिकी रात को पौने 12 बजे दर्ज की गई थी। इसमें पहले अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज किया गया था जबकि शव की स्थिति ही अपनी कहानी बता रही थी। आखिर इतनी देरी क्यों हुई और अस्वाभाविक मौत का मामला क्यों दर्ज किया गया था? उनका सवाल है कि अस्पताल से पीड़िता के घर फोन पर यह क्यों बताया गया था कि आपको बेटी बीमार है और उसने शायद आत्महत्या कर ली है? अब तक यह पता नहीं चल सका है कि किसने और किसके कहने पर वह फोन किया था।

नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025

अपर कलेक्टर ने ली राजनैतिक दलों की बैठक

निर्वाचन कार्यक्रम की दी विस्तृत जानकारी, सभा, रैली और जुलूस के लिए अनुमति लेना अनिवार्य

गणेश वैष्णव । सिटी चिफ (छग) नारायणपुर, छत्तीसगढ़ राय निर्वाचन आयोग द्वारा 20 जनवरी 2025 को नगरीय निकाय निर्वाचन तथा त्रिस्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन 2025 के लिए कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही नारायणपुर जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। अपर कलेक्टर ने बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई ने जिला कार्यालय के सभा कक्ष में राजनैतिक दलों की बैठक लेकर निर्वाचन कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। अपर कलेक्टर ने बताया कि जिले के नगरीय निकाय निर्वाचन दलीय आधार पर ईन्वीएम के माध्यम से मतदान संपन्न कराया जाएगा एवं त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन मतदान पत्र के माध्यम से चुनाव कराया जाएगा। नगरपालिका क्षेत्र के मतदान केंद्रों के लिए ईक्वीएम, व्हीक्वीपैट सहित अन्य प्रचार सामग्री का वितरण एवं जमा शासकीय बालक उत्तर माध्यमिक विद्यालय में किया जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव के लिए सामग्री का वितरण स्ट्रॉंग रूम से किया जाएगा। निर्वाचन के दौरान नारायणपुर में मतदान का कार्य अधिकारियों द्वारा संपन्न कराया जाएगा।

अपर कलेक्टर पंचभाई ने उपस्थित राजनीतिक दलों से आदर्श आचार संहिता के दायरे में गतिविधियां संचालित करने एवं सोशल मीडिया पर कोई भी आपत्ति जनक सामग्री पोस्ट नहीं करने का आग्रह किया। मतदान के लिए फोटोयुक्त दस्तावेजों का उपयोग करने की जानकारी दी गई, जिसमें आधार, पेन कार्ड, मतदान पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज आवश्यक होंगे।

नगरीय निकाय हेतु 22 से 28 जनवरी तक नाम निर्देशन जमा कर सकेंगे और 29 जनवरी को नामांकन जांच किया जाएगा। उम्मीदवार 31 जनवरी को नाम वापसी कर सकेंगे। 11 फरवरी को नगरीय निकाय में मतदान किया जाएगा तथा 15 फरवरी को परिणाम घोषित किया जाएगा। इसी प्रकार त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नाम निर्देशन 27 से 03 फरवरी तक जमा कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 04



फरवरी को किया जाएगा। उम्मीदवार 06 फरवरी को नाम वापसी कर सकेंगे। त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जिले में मतदान पहला चरण में 17 फरवरी और दूसरा चरण 23 फरवरी को होगा, इसके लिए मतगणना 18 और 24 फरवरी को किया जाएगा। नगरीय निकाय पार्षद के लिए 21 वर्ष से अधिक और अध्यक्ष के लिए 25 वर्ष से अधिक आयु होना अनिवार्य है। इसी प्रकार सरपंच एवं पंच के लिए 21 से अधिक आयुवर्ग होना अनिवार्य है।

नारायणपुर जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाना अथवा करवाया जाना निषिद्ध किया गया है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, प्रचार करने के लिए वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं में जहां निर्वाचन संपन्न होना है वहां प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही सक्षम अधिकारी के अनुमति पश्चात किया जा सकेगा। किंतु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण क्रिम के होंगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किये जायेंगे। लोक परिशांति को देखते हुए लम्बे चोंगे वाले लाउडस्पीकर का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। वाहनों एवं चुनावी सभाओं में एक से अधिक लाउडस्पीकर समूहों में लगाया जाना भी प्रतिबंधित किया जाता है। उपयोग से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन ना हो यह भी अनुमति प्राप्तकर्ता

सुनिश्चित करेंगे। नारायणपुर जिला अंतर्गत सभी क्षेत्रों में प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर सामान्यतः किया जा सकता है, परन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगरपालिका परिषद्, जनपद पंचायत एवं किसी अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है।

कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और नहीं आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमति न तो कोई सभा करेगा, न कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा और न ही कोई धरना देगा। यह आदेश जिले शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य सम्पादन के लिये लाठी या अस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें चुनाव व मतदान के दौरान, कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हे शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक होता है। आदेश का

उल्लंघन करने वाला व्यक्ति, दल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। जिला सीमा क्षेत्र में आग्नेय अस्त्र लायसेंसियों को आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 उपधारा (3) के उप क्लाज (बी), धारा-21 के तहत निर्दिशित किया गया है कि वे अपने अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 07 दिवस के भीतर जमा करें, इसके अतिरिक्त लायसेंसि अपने शस्त्र जिला नारायणपुर नगर के शस्त्र डीलर, जिनके पास शस्त्र डिपॉजिट करने अनुज्ञति है, वहां जमा कर सकते हैं, जो व्यक्ति शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करते हैं, उसकी सूचना भी संबंधित थाने में प्रदान करेंगे ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण न हो सके तथा इन अस्त्रों के दुरुपयोग होने से रोका जा सके। संबंधित शस्त्र डीलर थानेवार जानकारी तैयार कर संबंधित थाने एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। यह आदेश जिले में निवासरत सभी लायसेंसि तथा बाहर के जिले से आये लायसेंसि पर भी लागू होगा। सभी लायसेंसि आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि संध्या पवार, नरेन्द्र मैश्राम, इंद्र प्रसाद बघेल, इंजियन नेशनल कांग्रेस के प्रतिनिधि संजय राय, जय वट्टी, विजय सलाम, एडीसनल एसपी सुशील कुमार नायक, एसडीएम गौमत पाटिल, डिप्टी कलेक्टर डॉ. सुमित गर्ग सहित जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे।

उत्तर प्रदेश डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा

रघुवीर सिंह। सिटी चीफ (उप्र) महाकुंभ-2025 में, जहां गंगा की तरह आस्था और एकता संगम की तरह चमकती है, मुझे माँ गंगा की कृपा के लिए पवित्र जल में डुबकी लगाने का सौभाग्य मिला। पुलिस और प्रशासन के समर्पण और धर्मिरा के 'संगम' को सलाम करते हुए सभी के लिए सुरक्षित और शांति तीर्थयात्रा सुनिश्चित की।



मधुवन सेंथी लिंक रोड़ पर स्पीड ब्रेकर लगवाने को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

शंभूपुर। चित्तौड़गढ़ शहर के मधुवन क्षेत्र के नागरिकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप क्षेत्र में तेज गति से निकलने वाले वाहनों की गति कम करने को लेकर स्पीड ब्रेकर लगवाने की मांग की है। स्थानीय निवासी राजेन्द्र जांगिड़ ने बताया कि वार्ड नंबर 29 के मधुवन सेंथी लिंक रोड़ पर तेज गति से वाहन आते हैं इस वजह से आये दिन एक्सीडेंट होते हैं, यहां पर वाहनों की तेज गति से बहुत बार एक्सीडेंट होने से स्थानीय लोगों को डर बना रहता है, क्योंकि एक बार मधुवन के एक सीनियर नागरिक की शाम को टहलते वक्त तेज गति से आए वाहन ने टक्कर मार दी जिससे मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। अनेकों बार लोग तेज वाहनों से चोटिल हो गए हैं। ज्ञापन सौंप जिला कलेक्टर से निवेदन किया कि इस सम्बन्ध में निवर्तमान पार्षद के मार्फत अनेकों बार आयुक्त नगर परिषद चित्तौड़गढ़ को सूचित किया जा चुका है परन्तु



कोई सुध नहीं ली गई। वार्ड 29 के मधुवन सेंथी लिंक रोड़ पर चौराहे और साइड रोड के कट पर दो से तीन जगह पर अतिशीघ्र स्पीड ब्रेकर लगवाने की मांग की। ज्ञापन देते समय शिवजी शर्मा विजयपुर, सुधीर मेहता, कपी सिंह राणा, राजेंद्र जांगिड़, संजय मिश्रा, गोपाल शर्मा, रामसिंह सिसोदिया आदि उपस्थित रहे।

बालिकाओं की साईकिल रैली को विधायक जयंत मलैया ने हरीझण्डी दिखाकर किया रवाना

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रम

धीरज कुमार अहीरवाल । सिटी चीफ दमोह, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 वर्ष सफलता पूर्वक पूर्ण होने एवं 8 मार्च तक नए कार्यक्रमों के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय कार्यक्रम केआयोजन की शुरुआत जिला कलेक्ट्रेट परिसर से पूर्व वित्त मंत्री एवं दमोह विधायक जयंत कुमार मलैया एवं अपर कलेक्टर मीना मसराम ने बालिकाओं की साइकल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिसमें लगभग 250 से अधिक किशोरी बालिकाओं द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर से क्लिष्टाई नाका होते हुए बस स्टैंड तक बाल विवाह के विरुद्ध नारे एवं तख्ती के माध्यम से सन्देश जिसमें बाल विवाह कैसी नादानि जीवन भर आखों में पानी, आदि के द्वारा जन जागरूकता करते हुए पुरानी कलेक्ट्रेट में रैली का समापन किया गया। रैली में शहर परियोजना की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सेक्टर पर्यवेक्षकों ने भी बड़ चढ़कर हिस्सा लिया और बाल विवाह के विरुद्ध सन्देश दिए। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के निर्देशन में एवं जिला



कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जयवंत सिंह वर्मा के मार्गदर्शन में पुरानी कलेक्ट्रेट परिसर में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष प्रीति ठाकुर, गौरव पटेल की मौजूदगी में बालिकाओं द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसमें सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र रही कैदों की तलैया की शाला त्यागी बालिकाएं, जिन्होंने बाल विवाह जैसी कुरीति पर एक छोटी सी नाट्य प्रस्तुति से सभी की आखों में पानी भर आया। यह समाज को इस विषय पर सोचने पर मजबूर कर देने वाली लघु नाटिका थी। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष श्रीमती प्रीति ठाकुर

ने जिले के कलेक्टर का आभार व्यक्त करते हुये कहा एक सकारात्मक सोच जिससे आज पिछड़े हुए क्षेत्र से आने वाली बालिकाओं के सपनों को पंख देकर उनको एक नया माहौल दिया, हर एक बच्चे में प्रतिभाएं हैं, जरूरत है सिर्फ अवसर प्रदान करने का जो आज महिला एवं बाल विकास विभाग एवं सडमेप संस्था द्वारा इनको दिया गया इससे आज इनकी अन्दर छुपी प्रतिभाएं निकलकर बाहर आएंगी। गौरव पटेल ने कहा निश्चित ही बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना ने देश में बालिकाओं एवं महिलाओं की स्थिति में सुधार लाया है, आज हमें जरूरत है, लैंगिक भेदभाव को दूर करके बालिकाओं को भी शिक्षा, समाज और विभिन्न क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करने की। किसी भी बालिका को यदि आगे बढ़ने में यदि कोई कठनाई आगे है, तो वह उसके कर्ता भी मिल सकती है, मैं हर संभव प्रयास करूँगा उनकी समस्या का हल करने में। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर शपथ दिलाई गई।

सागर कमिश्नर डॉ. रावत ने बोर्ड परीक्षा में 30 प्रतिशत से कम परीक्षा परिणाम वाले 9 प्राचार्यों की वेतन वृद्धि रोकी

धीरज कुमार अहीरवाल । सिटी चीफ दमोह, सागर संभाग के कमिश्नर डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा के बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं 12वीं की 2023-24 की वार्षिक परीक्षा में 30 प्रतिशत से कम परीक्षा परिणाम वाले दमोह जिले के 9 प्राचार्यों की एक-एक वेतन वृद्धि आसंचयीरूप से रोकने के आदेश जारी किए हैं। संभाग आयुक्त डॉ वीरेन्द्र सिंह रावत ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की कक्षा 10वीं, 12वीं की परीक्षा में शतप्रतिशत परीक्षा परिणाम लाने के निर्देश दिए गए थे किंतु दमोह जिले के 9 विद्यालयों के परीक्षा परिणाम 30 प्रतिशत से कम रहे जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी के प्रस्ताव के बाद संबंधित प्राचार्य की एक-एक वेतन वृद्धि असंचर्ई रोकने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिन प्राचार्यों की एक एक वेतन वृद्धि रोकी गई उनमें शास. उत्कू.उ.मा. विद्यालय बटियागढ़ के प्राचार्य बी.एस. रावत की हाईस्कूल का परीक्षा परिणाम 2023-24 में 14.29 प्रतिशत,

जिला नारायणपुर में 5 लाख ईनामी 1 एसीएम सहित अन्य 7 जिसमें 3 पुरुष व 5 महिला कुल 8 माओवादियों का आत्मसमर्पण इन माओवादियों पर है 8 लाख से अधिक का ईनाम घोषित

गणेश वैष्णव । सिटी चिफ (छग) नारायणपुर, श्री सुन्दरराज पी. (भा.पु.से.) पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज जगदलपुर, श्री अमित तुकाराम काम्बले (भा.पु.से.) पुलिस उप महानिरीक्षक कांकेर रेंज कांकेर के मार्गदर्शन, श्री प्रभात कुमार (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक नारायणपुर एवं श्री रोबिनसन गुड्डिया (भा.पु.से.) अति. पुलिस अधीक्षक नारायणपुर के निर्देशन में नारायणपुर पुलिस द्वारा माओवादियों के विरुद्ध क्षेत्र में लगातार चलाये जा रहे नक्सल उन्मुलन अभियान और अति संवेदनशील अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार कैम्प स्थापित होने से पुलिस के बढ़ते प्रभाव व नक्सलियों के अमानवीय, आधारहीन विचारधारा एवं उनके शोषण, अत्याचार तथा बाहरी नक्सलियों के द्वारा भेदभाव करने तथा स्थानीय आदिवासियों पर होने वाले हिंसा से तंग आकर नक्सल संगठन से 1 एसीएम सहित अन्य 7 माओवादी कुल 8 के आत्मसमर्पण की महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिनमे

1 . दिलीप ध्रुवा पिता स्व. बुकलू उम्र 54 वर्ष निवासी ग्राम फरसगांव/बेदरे थाना कुटरू वर्तमान पता- कोडतामरका पंचायत धुरबेड़ा थाना कोहकामेटा जिला नारायणपुर (छग0) पद- एसीएम कुतुल एरिया कमेटी इंटेेलीजेंस प्रभारी, 05 लाख ईनामी।

2 . सुकली उर्फ ललिता तिमसा पिता काना उम्र 25 वर्ष जाति माडिया निवासी ग्राम पोदमकोटी थाना कोहकामेटा जिला नारायणपुर(छग0) पद- कुतुल एलओएस सदस्य, 01 लाख ईनामी।

3 . सुधराम पोयाम पिता सुकड़ो उम्र 17 वर्ष जाति माडिया निवासी ग्राम श्रुलश्रुली/जुवाड़ा थाना ओरछा जिला नारायणपुर (छग0) पद- ओरछा एलओएस सदस्य दीपक का गाई, 01 लाख ईनामी।

4 .सोनी कोराम पिता स्व. बुधु कोराम उम्र 22 वर्ष जाति माडिया निवासी ग्राम भटबेड़ा पंचायत मण्डाली थाना ओरछा जिला नारायणपुर (छ.ग.) पद- जाटलूर एलओएस सदस्य, 01 लाख ईनामी।

5 .मंगलू कश्यप पिता स्व. अड़मो उम्र 41 वर्ष जाति अबुझमाडिया निवासी ग्राम बेड़ामेटा पंचायत कुतुल थाना कुटड़ाझोर जिला नारायणपुर (छ0ग0) पद- कोडलियार जनताना सरकार अध्यक्ष।

6 .घस्सी उर्फ पुत्री पोडियाम पिता स्व. बीमा उम्र 27 वर्ष जाति गोड़ निवासी ग्राम मोहनार पंचायत पंचायत मण्डाली थाना धनोरा जिला नारायणपुर (छ0ग0) पद- इन्द्रवती एरिया सीएनएम सदस्या। 7 . अमृता नुरेटी पिता अड़वे राम उम्र 18 वर्ष जाति माडिया निवासी गारपा पंचायत गारपा थाना सोनपुर जिला नारायणपुर (छ0ग0) पद ईरकभट्टी नाटय चेतना मंच।

8 .सुदनी वड़दा पिता मंगतु राम वड़दा उम्र 17 वर्ष जाति माडिया निवासी ग्राम कोडलियार थाना कोहाकमेटा जिला नारायणपुर



(छ0ग0) पद- रेकावाया जनताना सरकार स्कूल में विद्यार्थी न्यू रिकरूट। के आत्मसमर्पण हेतु प्रोत्साहित कराने में नारायणपुर पुलिस, डीआरजी, आईटीबीपी का विशेष प्रयास रहा है। आज दिनांक 22.01.2025 को 05 लाख ईनामी (एसीएम) दिलीप ध्रुवा माड़ु डिवीजन के अंतर्गत कुतुल एरिया कमेटी समेत सुकली उर्फ ललिता (एलओएस सदस्य), सुधराम पोयाम(एलओएस सदस्य), सोनी कोराम (एलओएस सदस्य), मंगलू कश्यप (आरपीसी), घस्सी उर्फ पुत्री (सीएनएम), अमृता नुरेटी (सीएनएम), सुदनी वड़दा(न्यू रिकरूट) ने श्री प्रभात कुमार पुलिस अधीक्षक नारायणपुर (भा.पु.से.), श्री रोबिनसन गुड्डिया (भा.पु.से.) व श्री सुशील नायक (रा.पु.से.) अति. पुलिस अधीक्षक जिला नारायणपुर के समक्ष बिना हथियार के आत्मसमर्पण किये। आत्मसमर्पण करने पर प्रोत्साहन राशि 25 हजार रुपये का चेक प्रदान किया गया एवं उन्हें नक्सल उन्मुलन नीति के तहत मिलने वाली सभी प्रकार की सुविधाएं दिलाया जायेगा। इस अवसर पर पुलिस विभाग नारायणपुर के अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

माओवादियों द्वारा आत्मसमर्पण के पीछे माड़ु और नारायणपुर जिले में चलाये जा रहे विकास कार्य बड़ा कारण रहा तेजी से बनती सड़कें, गावों तक पहुँचती विभिन्न सुविधाओं ने इन्हें प्रभावित किया है। सुरक्षा बलों के लगातार अंदरूनी क्षेत्रों में कैम्प स्थापित करने एवं क्षेत्र में चलाये जा रहे आक्रामक अभियानों एवं मोर्चे जाने से उत्पन्न भय ने भी इन्हें संगठन छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। संगठन के विचारों से मोहभंग एवं मिली निराशा, संगठन के भीतर बढ़ते आंतरिक मतभेद तेलंगाना-आंध्र कैडर के नक्सलियों के दबाव पूर्वक कार्य कराने की नीति के चलते इन नक्सलियों को यह महसूस हुआ कि वे व्यर्थ ही अपने ही लोगों को मार रहे थे। छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति ने उन्हें नई उम्मीद दी है और वे जंगल की जिला नारायणपुर (छ0ग0) पद- इन्द्रवती एरिया सीएनएम सदस्या। 7 . अमृता नुरेटी पिता अड़वे राम उम्र 18 वर्ष जाति माडिया निवासी गारपा पंचायत गारपा थाना सोनपुर जिला नारायणपुर (छ0ग0) पद ईरकभट्टी नाटय चेतना मंच। 8 .सुदनी वड़दा पिता मंगतु राम वड़दा उम्र 17 वर्ष जाति माडिया निवासी ग्राम कोडलियार थाना कोहाकमेटा जिला नारायणपुर

विगत वर्ष सुरक्षा बलों द्वारा चलाये गए सघन नक्सल विरोधी अभियान ने जहाँ शीर्ष नेतृत्व को झिंझोड़कर रख दिया है वहीं अपनी नाकामियों का ठीकना उन्होंने बीच

के व निचले कैडर पर छोड़ दिया है। सभी माओवादियों ने सरेंडर के दौरान बातचीत में यह भी बताया कि नक्सल संगठन के कई सदस्य भी वर्तमान में आत्मसमर्पण करना चाह रहे किन्तु शीर्ष कैडर के दबाव के चलते वे अपनी मुख्यधारा से संपर्क नहीं कर पा रहे। अंदरूनी क्षेत्र में लगातार पुलिस कैम्प खुलने एवं आक्रामक नक्सल विरोधी अभियान संचालित होने से पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है और नक्सलियों के खोखले विचारधारा व क्रूर व्यवहार, आंतरिक मतभेद से बाहर निकलकर समाज के मुख्य धारा जुड़ने के लिए प्रेरित हो रहे हैं जो कि माड़ु डिवीजन के अंतर्गत कुतुल एरिया कमेटी दिलीप ध्रुवा (एसीएम) सहित अन्य छोटे कैडर के 07 माओवादियों का आत्मसमर्पण इसी का परिणाम है। आने वाले समय में और भी नक्सलियों के संगठन छोड़कर आत्मसमर्पण करने की गोपनीय आसूचना है। इस प्रकार बहुत अधिक संख्या में नक्सलियों का आत्मसर्पण से शीर्ष माओवादी कैडर के लिए बड़ा नुकसान हुआ है। नक्सल मुक्त माड़ु बचाव अभियान की कल्पना साकार रूप लेते हुए। नारायणपुर एसपी श्री प्रभात कुमार (भा.पु.से.) द्वारा नक्सलियों के शीर्ष नेतृत्व के दबाव में आकर नक्सली संगठन से जुड़े ग्राम स्तर/पंचायत स्तर/ एरिया स्तर के बड़े व छोटे कैडरों से अपील किया गया कि वे भय मुक्त होकर आत्मसमर्पण कर शासन की पुर्नवास योजना का लाभ लेवें अन्यथा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा छ शासन की पुनर्वास नीति के फायदे घर, नौकरी ने इन्हें आकर्षित किया है। इन्होंने आत्मसमर्पण माड़ु एवं खुद की भलाई के लिए किया है, उन्होंने अनुभव किया कि केवल शीर्ष नेतृत्व के दबाव में आकर उन्होंने माड़ु के लोगों को प्रताड़ित किया और लोग उनका साथ छोड़ते चले गये है, जहाँ नक्सलियों का शीर्ष नेतृत्व भी अब उनकी विचारधारा के साथ नहीं बल्कि खिलाफ है, यह द्वन्द सालों से इनके भीतर रहा है लेकिन माड़ु बचाओ अभियान उन्हें अब एक नई आस दी है। माओवादी की विचारधारा में भटके नक्सलियों को उनके घर वाले भी वापस लाना चाहते हैं। हम सभी नक्सली भाई-बहनों से अपील करते हैं कि उनका बाहरी लोगों की भ्रामक बातों और विचारधारा से बाहर निकलने का समय आ गया है, अब समय माड़ु को वापस उसके मूलवासियों सौंप देने का है जहाँ वे स्वच्छन्द रूप से अपना नैसर्गिक जीवन जी सके।



परीणाम 2023-24 में 11.86 प्रतिशत,हायर सेकेण्डरी स्कूल 30 प्रतिशत आने पर, शास.उ.मा.विद्यालय मडियापूर के प्रभारी प्राचार्य ममता छिरौतिया की हाईस्कूल का परीक्षा परिणाम 2023-24 में 28.30 प्रतिशत आने पर, शास.उ.मा.विद्यालय तेजगढ़ के प्रभारी प्राचार्य अनरथ की सिंह ठाकुर की हाईस्कूल का परीक्षा परिणाम 2023-24 में 21.47 प्रतिशत आने पर आसंचयीरूप से वेतन वृद्धि रोकी गई है। कमिश्नर डॉक्टर वीरेन्द्र

सिंह रावत ने संभाग के समस्त प्राचार्य एवं शिक्षकों से आवाह किया है कि अपने-अपने विद्यालय का बोर्ड परीक्षा का परीक्षा परिणाम सत्र 24-25 का शत प्रतिशत हो इसके लिए रेमेडियल कक्षाओं के माध्यम से छात्र-छात्राओं की समस्याओं का निदान करें। उन्होंने कहा कि सभी कलेक्टर अपने-अपने जिलों में छात्र-छात्राओं की समस्याओं एवं उनके तनाव को दूर करने के लिए एक-एक कंट्रोल रूम भी स्थापित करें जिससे कि छात्र-छात्राएं अपनी समस्याओ को हल करा सकें। उन्होंने सभी प्राचार्य को निर्देश दिए की सभी प्राचार्य अपने विद्यालय की कक्षा दसवीं एवं बारहवीं की कक्षाओं का पाठ्यक्रम पूर्ण करें जिससे कि विद्यार्थियों को परीक्षा में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।इन्होंने संभाग के समस्त कलेक्टर एवं समस्त शिक्षा शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया कि विद्यालयों का सघन निरीक्षण करें । जिससे आगामी परीक्षाओ में बेहतर परिणाम परीक्षा परिणाम हासिल हो।

प्रधानमंत्री आवास योजना में फिर से शुरू होगा सर्वे, नए नाम जोड़े जाएंगे

ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र हितग्राहियों का सर्वे शुरू कराएगी जिला पंचायत, तैयारियां शुरू

धीरज कुमार अहीरवाल । सिटी चीफ दमोह, प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की देश के गरीब व जरूरतमंद लोगों को अपना घर उपलब्ध कराने की योजना है। इस योजना के तहत लाभार्थी को सब्सिडी प्रदान की जाती है ताकि हिंगराही आसानी से अपना घर बना सके। इस योजना को गांवों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नाम से संचालित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में योजना का लाभ देने के लिए जिला पंचायत द्वारा पात्र हितग्राहियों का सर्वे 17 जनवरी 2025 से प्रारंभ हो गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अर्पित वर्मा ने बताया कि यह सर्वे उन लोगों के लिए किया जाएगा जिन्होंने पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत आवेदन किया है। सर्वे के बाद पात्र व्यक्तियों का नाम पीएम आवास योजना की लाभार्थी सूची में शामिल किया जाएगा और मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता

प्रदान की जाएगी।
हीराग आवास योजना का ऐसे
दोषका सर्वे सीईओ जिला पंचायत
 अर्पित वर्मा ने बताया प्रधामंत्री
 आवास योजना ग्रामीण के तहत
 एक माह में सर्वे का काम पूरा
 करने का लक्ष्य रखा गया है। खास
 बात यह है कि इस बार लाभार्थी
 को अपनी पसंद का मकान बनवाने
 का ऑप्शन भी दिया गया है। सर्वे
 के बाद सभी पंचायतों से योग्य
 लाभार्थियों की सूची तैयार करके
 ग्रामीण विकास विभाग को भेजी
 जाएगी। इसके बाद यहां से सूची
 को प्रखंडवार तैयार कर मुख्यालय
 को भेजी जाएगी। इसके बाद वहां
 से जिले का प्रखंडवार लक्ष्य
 निर्धारित कर लाभार्थियों को
 आवास बनाने के लिए राशि
 उपलब्ध कराई जाएगी। शासन स्तर
 से प्रधानमंत्री आवास योजना
 ग्रामीण के तहत इस बार लाभार्थी
 को अपनी पसंद का मकान बनाने
 का मौका दिया गया है। योजना के
 तहत आवास प्लस ऐप में पसंद का
 मकान बनाने का ऑप्शन दिया गया

हे। आप जिस डिजाइन का मकान बनाना चाहते हैं इसका डिजाइन फेस डिटेक्शन के साथ एप में फोड हो जाएगा। लाभार्थी को मकान बनाने के लिए राशि 1.20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता चार किस्तों में सीधे हितग्राही के बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।

पीएम आवास योजना के नियमों में भी मिलेगी छील उन्होंने बताया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की इस बार जारी की गई संशोधित नई गाइडलाइन के अनुसार जिन लाभार्थियों के पास दो पहिया वाहन है, उन्हें भी पीएम आवास योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा यदि किसी परिवार का कोई सदस्य 15 हजार रुपए प्रतिमाह कमाता है, तो भी उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। पहले 10 हजार रुपए प्रतिमाह कमाने वाले व्यक्ति को ही इसमें आवेदन के लिए पात्र माना जायेगा। योजना के नियमों में छील दिए जाने से अब अधिक जरूरतमंद और गरीब व्यक्ति तक

इस योजना का लाभ पहुंच सकेगा।
ऐसे मिलनेगी किस्त की राशि
 योजना में ग्रामीण के तहत सरकार की ओर से लाभार्थी को मकान बनाने के लिए चार किस्तों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसमें पहली किस्त में 25 हजार रुपए, दूसरी किस्त में 40 हजार रुपये तीसरी किस्त में 40 हजार एवं चतुर्थ/अंतिम किस्त 15 हजार रुपए प्रदान किए जाते हैं। मनरेगा के तहत मजदूरी की राशि मनरेगा पोर्टल से जारी की जायेगी यह राशि सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाती है। इसके लिए उन्हें अपने मकान का काम निष्पत्ति समय में पूरा करना होता है। पहली किस्त मिलने के बाद हितग्राही को भवन निर्माण शुरू करना होता है। इसके बाद दूसरी किस्त मिलती है। जब भवन का काम छत लेवल तक पहुंच जाता है तब लाभार्थी को तीसरी किस्त का भुगतान किया जाता है एवं पूर्णता के बाद अंतिम किस्त प्रदाय की जाती है।

गरियाबंद में सुरक्षाबलों का बड़ा ऑपरेशन 20 से ज़्यादा नक्सली ढेर

2 जवान घायल, अमित शाह बोले- नक्सलवाद का अंत करीब



राजीव खरे । सिटी चीफ़ (छा) ।
गरियाबाद, छत्तीसगढ़ के गरियाबादवंद बेल्ट
जिले के कुहाड़ा घाट स्थित भालू
छिन्नी के जलानों में सुरक्षाबलों
और नक्सलियों के बीच तीन दिनों
तक चला बढ़ा ऑपरेशन समाप्त हो
गया। इस अभियान में सुरक्षाबलों
ने 20 से भी दूरे नक्सलियों को मार
गिराया। मारे गए नक्सलियों में 1
करोड़ रुपये का इनामी सेंट्रल
कमेटी मेंबर (एचएस) बालकृष्ण और
उसके 25 साथी शामिल हैं।
इस ऑपरेशन में सुरक्षाबलों को
बड़ी कामयाबी मिली, लेकिन
मुठभेड़ के दौरान दो जवान घायल
हो गए। 20 जनवरी को, एसओजी
(स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) के एक
जवान को पैर में गोली लगने के
बाद रायपुर एयरलिफ्ट किया गया।
जबकि 21 जनवरी को, एसओजी
नुआपाड़ा का एक और जवान
घायल हुआ, जिसे रायपुर में भर्ती
कराया गया। डॉक्टरों ने दोनों की
स्थिति सामान्य बताई है। मुठभेड़ के
बाद सुरक्षाबलों ने 14 नक्सलियों
के शव रायपुर के मेकाहारा

असत्ताल पोस्टमार्टम के लिए भेजे। इनमें 6 महिलाएं और 8 पुरुष शामिल हैं।

गरियाबंद के अलावा छत्तीसगढ़ के सुकमा, दंतवाड़ा, बीजापुर, बस्तर और नारायणपुर जिले लंबे समय से नक्सली गतिविधियों से प्रभावित रहे हैं। इन इलाकों में घने जंगल और दुर्गम इलाके नक्सलियों के छिपने और रणनीति बनाने में सहायक होते हैं। पर राय में विष्णुदेव सरकार आने के बाद से मुख्यमंत्री व गृहमंत्री के निर्देशों पर सुकमाबलों की लगातार दबिश बढ़ती जा रही है और एक के बाद एक सफल ऑपरेशन की वजह से नक्सलियों में घबराकर फैल रही है। हाल में ही नारायणपुर जिले में 8 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। संदर्भ करने वालों में कुतुल एरिया कमेटी के इंटील्लिजेंस प्रभारी दिलीप ध्रुवा भी शामिल है।

ऑपरेशन की सफलता पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सुकमाबलों की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए कहा, देश में नक्सलवाद अपनी

आखिरी साँसें गिन रहा है। केंद्र और राय सरकारों इसे पूरी तरह खतम करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। उन्होंने घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऑपरेशन का सफलता पर सुरक्षाबलों को बधाई दी। उन्होंने कहा, यह सफलता नक्सलियों के खाते की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति और विकास सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। गरियाबंद ऑपरेशन ने यह साबित कर दिया है कि नक्सलवाद अब कमजोर पड़ रहा है। 27 नक्सलियों का मारा जाना और 8 का संदेह करना यह दिखाता है कि सुरक्षाबलों की रणनीति और सरकार की पुनर्वास योजनाएँ प्रभावी हो रही हैं। घायल जवानों की बहादुरी और सुरक्षाबलों की रणनीति ने छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है।

महाकुम्भ में त्रिवेणी तट पर बड़ा फैसला

काशी तक आएगी गंगा एक्सप्रेस-वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से भी होगी कनेक्ट

रघुवीर सिंह। सिटी चीफ (उ प्र) महाकुम्भनगर, तीर्थहार प्रयाग में 144 वर्ष के बाद महाकुम्भ के शुभ संयोग पर लोककल्याण का संकल्प लेकर बैठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाले सरकार ने राय में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बड़े फैसले लिए हैं। पावन त्रिवेणी तट पर हुई कैबिनेट की ऐतिहासिक बैठक में 320 किलोमीटर लंबाई वाले विन्ध्य एक्सप्रेसवे और 100 किमी लंबाई वाले विन्ध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को सैद्धांतिक सहमति दी गई। विशेष कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित और प्रकरण एक्सप्रेसवे के माध्यम से कनेक्टिविटी नेटवर्क विकास और क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनाओं का विकास हो रहा है। वर्तमान में प्रदेश के पश्चिमांचल, मध्यांचल, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र एक्सप्रेसवे से आछादित हैं और अब दूरवर्ती दक्षिणी-पूर्वी विन्ध्य क्षेत्र में सामाजिक-एवं आर्थिक विकास के लिए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाना आवश्यक है। इस दृष्टि से प्रयागराज मोजापुर, वाराणसी, चंदौली एवं सोनभद्र को जोड़ते हुए 320 किलोमीटर लंबाई



वाले नए नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाना चाहिए। इस नए एक्सप्रेस में का प्रारंभ बिंदु, प्रयागराज में गंगा एक्सप्रेसवे होगा, जबकि सोनभद्र में एएच 39 पर इसका समापन होगा। इस तरह गंगा एक्सप्रेसवे और विंध्य एक्सप्रेसवे की मधी कनेक्टिविटी होगी, साथ ही, सोधी प्रदेश छाँसीगढ़ में झारखंड से भी अक्षांश संपर्क स्थापित हो सकेगा। इसी प्रकार, विंध्य एक्सप्रेसवे पर चंडौली से प्रारंभ होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अंतिम बिंदु गाजीपुर तक विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे वे का

निर्माण किया जाना उचित होगा। इसकी लंबाई लगभग 100 किमी होगी। प्रयागराज को बढ़ा उधार देने हेतु मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में सलौरी से हेतापट्टी तक नया ब्रिज के निर्माण को भी आवश्यकता जताई। उक्त के साथ ही बैठक में साथ ही शास्त्री ब्रिज और यमुना सिनेचर ब्रिज के समानांतर नया ब्रिज को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह तीनों ब्रिज स्मार्ट प्रयागराज को प्रतिकल्पना को आकार देने वाले होंगे। त्रिवेणी तट पर हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरी

सरकार ने सुरक्षित और समृद्ध उत्तर प्रदेश के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। त्रिविणी ताप-पाप नाशिनी गंगा, कर्मवाहिनी यमुना और अंतःसलिला सरस्वती के पावन संगम तट पर एकजुट पूरी योगी सरकार ने राय के गरीब युवाओं, किसान और महिलाओं के हित में कई निर्णय लिए। गंगा तीरे बने त्रिवेणी संकुल में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री द्वय के साथ सभी कैबिनेट मंत्री, राय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और राय मंत्री गणों की उपस्थिति रही।

**हरीझण्डी दिखाकर किया
स्वाना
बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ
योजना के 10 वर्ष पूर्ण होने
पर
आयोजित हुए विभिन्न
कार्यक्रम**

शुरूआत जिला कलेक्ट्रेट परिसर से पूर्व वित्त मंत्री एवं दमोह विधायक पूर्व मंत्री जयंत कुमार मलैया एवं अपर कलेक्टर मोना मसराम ने बालिकाओं की साइकल रैली को। हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिसमें लगभग 250 से अधिक किशोरी बालिकाओं द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर से किलाई नाका होते हुए बस स्टैंड तक बाल विवाह के विरुद्ध नारे एवं तख्ती के माध्यम से सन्देशों जिसमें बाल विवाह कैसी नानादी जीवन भर आशंका में पानी, आदि के द्वारा जन जागरूकता करतें हुए पुरानी कलेक्ट्रेट में रैली का समापन किया।

गया। रैली में शहर परियोजना के आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सेक्टर पर्यवेक्षकों ने भी बड़ चढ़कर हिस्सा लिया और बाल विवाह के विरुद्ध सन्देश दिए। कलेक्टर सुधीर कुमा कोचर के निर्देशन में एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जयवंत सिंह वर्मा के मार्गदर्शन में पुरानी कार्यक्रेटर परिसर में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष प्रीति ठाकुर, गौरव पटेल की मौजूदगी में बालिकाओं द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किया।

महाकुंभ में अतिशीघ्र शुरू होगी एक और हेलीकाप्टर सेवा

ईको टूरिज डेवलपमेंट बोर्ड ने कराया ट्रायल, बोट क्लब के पास से भरेगा उड़ान

सुधवीर सिंह। सिटी चीफ (उ प्र)

महाकुंभ नगर, उत्तर प्रदेश ईको दूरिम डेवलपमेंट बोर्ड की ओर से शीघ्र हेलीकाप्टर सेवा भी शुरू की जाएगी, जिसका ट्रायल हो चुका है। श्रद्धालु आसमान की उंचाइयों से महाकुंभ के दर्शन के साथ-साथ राय की समृद्ध प्राकृतिक विरासत से परिचित होंगे।

यह जानकारी पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में ईको दूरिम शिखर पर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जायेगी। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को वाय राइड का आनंद देने के लिए पहले से एक हेलीकाप्टर संचालित किया जा रहा है। पर्यटकों की रुचि को देखते हुए ईको दूरिम डेवलपमेंट बोर्ड ने एक समझौता किया है। अतिशीघ्र एक और हेलीकाप्टर सेवा शुरू की जायेगी, जिसका ट्रायल हो चुका है। यह सेवा महाकुंभ नगर में बोट क्लब के पास स्थित हेलीपोर्ट से संचालित होगी। पर्यटक 1296 रुपये में 7-8 मिन्ट तक भ्रमण करेंगे। इसकी बुकिंग बोर्ड की वेबसाइट 222.६६७४८३५७९३.६७३ से की जा सकती है। हेलीकाप्टर में उड़ान के साथ ही प्रदेश के महत्वपूर्ण ईको साइट्स के बारे में विभिन्न माध्यमों से पर्यटकों को



बताया जाएगा।
श्री जयवीर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश धार्मिक आध्यात्मिक रूप से जितना महत्वपूर्ण है उतना ही प्राकृतिक रूप से भी। भारत के स्वीट्जरलैंड के नाम से विख्यात सोनभद्र, जहां पर 1400 मिलियन वर्ष पुराना सलखन फासिलस पार्क जैसे कई आकर्षण हैं। रानी टाइगर रिजर्व, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कतरिनीयाघाट वाइल्ड लाइफ सैंक्युरी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व सहित अनेकों आकर्षण हैं जो तीर्थ नगरी से मामूली दूरी पर स्थित है। इन्हें टूरिज्म बोर्ड की ओर से महाकूच में

3250 वांगफोट में लगाई प्रदर्शनी में इन सभी आकर्षणों को प्रदर्शित किया जा रहा है। ताकि पर्यटक इन स्थानों पर भी भ्रमण के लिए आकर्षित हों। प्रदर्शनी में आगंतुकों के लिए ईको टूरिज्म सेल्फी पॉइंट्स, वचुअल रियलिटी डोम, ईकोटूरिज्म डेस्टिनेशंस एवं ईकोटूरिज्म विकास बोर्ड द्वारा किए जा रहे कार्यों को प्रस्तुत किया जाएगा। ईकोटूरिज्म से संबंधित विभिन्न हितधारकों द्वारा प्रचार, प्रसार एवं जानकारी प्रदान की जाएगी।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि हम पर्यटन

स्थलों पर अछी कनेक्टिविटी देने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा लखनऊ से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए हेली सर्विस का संचालन किया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ से 5000 रुपये में पर्यटक दुधवा पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग से जहां 4 घंटे से अधिक समय लगता है वहीं वायुमार्ग से एक घंटे में ही यात्रा पूरी होगी। आप www.uy.flyola.in और www.upecboard.in पर बुकिंग कर सकते हैं।



रघुवीर सिंह। सिटी चीफ (उ.प्र.) महाकुभनगर, भारत तथा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, शहरों की ओर बढ़ते हुए पलायन के कारण नगरीय जनसंख्या को बेहतर अवस्थापना सुविधाएं तथा विकास के अवसर प्रदान करने की चुनौती है। अतः नगरीय निकायों को बेहतर अवस्थापना सुविधाएं यथा- पेयजल, सड़क, ड्रेनेज, पथ- प्रकाश आदि प्रदान करने के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है। वित्तीय सुदृढ़ीकरण के लिए निकायों की विभिन्न वित्तीय स्रोतों से धनराशि की आवश्यकता होती है। विभिन्न

वित्तीय स्रोतों से प्राप्त धनराशि के उपयोग में वित्तीय अनुशासन एवं प्रबन्धन एक महत्वपूर्ण कड़ी है।
अतः निकायों में सुदृढ़
राजकोषीय प्रबन्धन,
M a r k e t
Orientation एवं
Credit Worthiness
बढ़ाने के लिए भारत सरकार की
प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत
Municipal Bond निर्गत
करने के लिए प्रोत्साहित करते
हुए धनराशि भी उपलब्ध करायी
जा रही है।

उप्र० के नगर विकास एवं ऊर्जा
मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने बताया
कि इस प्रकार नगर निगम
प्रायगराज में ₹० 50 करोड़,
आगरा में ₹० 50 करोड़ तथा
वाराणसी में ₹० 50 करोड़ के

Municipal Bond
निर्गत करने की मंजूरी बुधवार को प्रयागराज महाकुम्भ में हुई। कैबिनेट की बैठक में मिली है।
उक्त नगर निगमों द्वारा नगर निगम सदन का अनुमोदन प्राप्त करते हुए परियोजनाओं का चयन कर लिया गया है।
इसके अतिरिक्त प्रयागराज में नगर निगम विभाग 100 करोड़ रुपये के खर्च से पण्डे के टक्कर का अस्पताल बनाएगा। यह जिले का पहला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल होगा।
साथ ही वाराणसी में अंडरग्राउंड पार्किंग सहित कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का विकास किया जाएगा। आगरा में सोलर सिटी और वॉटर ट्रीटमेंट का कार्य किया जाएगा।

ऑटो रिकशा चालक की बीच सड़क चाकू मारकर की हत्या

दिनदिहाड़े दिया घटना को अंजाम

नेशनल डेस्क. तेलंगाना से दिन दिहाड़े एक निर्मम हत्या की घटना का मामला सामने आया है। तेलंगाना के हनमकोंडा जिले में एक व्यक्ति ने दूसरे शख्स को सरेआम चाकूओं से गोद दिया। बताया जा रहा है कि जिस इलाके में यह घटना हुई वह अक्सर ही काफी व्यस्त रहता है। जब इसका

हत्यारे ने इस घटना को अंजाम दिया तो उस समय वहां पर खड़े लोग इसे तमाशा समझकर देख रहे थे। मृतक माडीकोंडा इलाके का रहने वाला था और इसका नाम मचारला राजकुमार बताया जा रहा है। वह पेशे से एक रिकशाचालक है और आसपास के गांवों में टेंट हाउस का

व्यवसाय भी करता था। हत्यारा भी पेशे से एक रिकशाचालक है। इस पूरी घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। इसमें देखा जा सकता है कि सड़क किनारे राजकुमार अपनी ऑटोरिकशा में बैठे हुए हैं, तभी वेंकटेश्वरालु बीच सड़क में अपनी रिकशा खड़ी करते हैं। इतने में



राजकुमार के पास पहुंचते हैं। इसके बाद दोनों में बहस होती है, जिसके बीच वेंकटेश्वरालु चाकू निकाल लेते हैं और राजकुमार पर वार करने लगते हैं। घटना को लेकर पुलिस का कहना है कि राजकुमार का एक महिला के साथ विवाहेत्तर सम्बंध था। इसी शक के चलते वेंकटेश्वरालु ने उसकी हत्या की। आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरु की जा चुकी है।

ट्रंप का एक और विवादित फैसला

DEI विभाग पर गिराई गाज, जबरन पेड लीव पर भेज दिया सारा स्टाफ

इंटरनेशनल डेस्क. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही कई बड़े और विवादित फैसले लिए। अब उन्होंने एक और बड़ा कदम उठाते हुए संघीय सरकार के विविधता, समानता और समावेशन (छथ्रडू) विभाग के सभी कर्मचारियों को पेड लीव पर भेजने का आदेश दिया है। इसके साथ ही इन कर्मचारियों को नौकरी से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के संकेत भी दिए हैं। ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के तुरंत बाद कई कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। इनमें एक महत्वपूर्ण आदेश छथ्रडू विभाग के कर्मचारियों को प्रभावित करता है। कार्मिक प्रबंधन कार्यालय द्वारा मंगलवार को जारी ज्ञापन में संघीय एजेंसियों को निर्देश दिया गया कि DEI कार्यालयों के कर्मचारियों को शाम 5 बजे तक पेड लीव पर भेजा जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि छथ्रडू कर्मचारियों को हटाने की योजना तैयार की जाए। साथ ही, किसी भी छथ्रडू कार्यक्रम को जारी रखने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। स फैसले से भेदभाव रोधी ट्रेनिंग और अल्पसंख्यक किसानों को मिलने वाली वित्तीय मदद पर सीधा असर पड़ेगा। ट्रंप के आदेश के बाद छथ्रडू से संबंधित सभी वेबपेज बंद कर दिए गए हैं। संघीय एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे छथ्रडू कर्मचारियों की सूची तैयार करें और उनके खिलाफ बल में कटौती की प्रक्रिया तेज करें।



संघीय एजेंसियों को गुरुवार तक छथ्रडू विभाग के कर्मचारियों की सूची तैयार करने और अगले शुक्रवार तक कटौती की कार्रवाई शुरू करने की उम्मीद है। ज्ञापन में कहा गया है कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपने कार्यकाल के दौरान छथ्रडू कार्यक्रमों के जरिए भेदभावपूर्ण नीतियों को बढ़ावा दिया। ट्रंप ने इन कार्यक्रमों को संघीय सरकार पर अत्यधिक बोझ बताते हुए बंद करने का फैसला किया। इस ज्ञापन की जानकारी

सबसे पहले सीबीएस न्यूज ने दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप सरकार का यह कदम बाइडन प्रशासन की नीतियों के खिलाफ एक स्पष्ट प्रतिक्रिया है। ट्रंप के इस फैसले से संघीय सरकार में DEI विभाग की भूमिका लगभग समाप्त हो जाएगी। हालांकि, यह कदम भेदभाव के खिलाफ काम करने वाले संगठनों और नागरिक अधिकार समूहों के बीच विवाद का कारण बन सकता है।

ट्रंप ने कनाडा खिलाफ किया जंग का ऐलान !

टूडो ने दिया कड़ा जवाब, कहा- हम युद्ध को तैयार...अमेरिका को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत

इंटरनेशनल डेस्क. अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जिसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन टूडो ने इसे लेकर कड़ा जवाब देते हुए कहा कि कनाडा ऊर्जा क्षेत्र में एक सुपरपावर है और उसके पास तेल और खनिज के ऐसे भंडार हैं जिनकी अमेरिका को जरूरत है। टूडो ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर जरूरत पड़ी तो कनाडा तेजी से और मजबूत जवाबी कार्रवाई करेगा।

ट्रंप की धमकी

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में यह वादा किया था कि वह अमेरिका और मेक्सिको पर 1 फरवरी से टैरिफ लागू करेंगे। उनका दावा है कि इससे अमेरिका को एक स्वर्ण युग मिलेगा और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उबारने में मदद मिलेगी। इस धमकी के बाद, ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर भी टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिसके खिलाफ जस्टिन टूडो ने विरोध जताया है।

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन टूडो



और अल्बर्टा प्रांत के नेता दोनों का मानना है कि कनाडा 25 प्रतिशत टैरिफ से बच सकता है। टूडो ने कहा, कनाडा एक ऊर्जा महाशक्ति है और हमारे पास तेल और महत्वपूर्ण खनिज हैं, जिनकी अमेरिका को जरूरत है। उनका यह बयान सीधे तौर पर ट्रंप के अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के वादे पर था। टूडो ने यह भी कहा कि अगर टैरिफ लागू हुए तो कनाडा पहले से भी तेज और मजबूत प्रतिक्रिया देगा।

ऑटोरियो के प्रमुख डौग फोर्ड ने कहा कि टैरिफ लागू होने की

स्थिति में कनाडा पूरी तरह से आर्थिक युद्ध के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, ट्रंप ने कनाडा के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा की है, और हम अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए अपने टूल बॉक्स में मौजूद हर उपकरण का इस्तेमाल करेंगे। फोर्ड ने यह भी कहा कि जैसे ही टैरिफ लागू होंगे, वह ऑटोरियो के शराब नियंत्रण बोर्ड को आदेश देंगे कि वे सभी अमेरिकी निर्मित शराब को अलमारियों से हटा लें। उनका दावा है कि कनाडा दुनिया में शराब के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है,

और यह कदम अमेरिका के लिए एक संदेश होगा।

जवाबी कार्रवाई का भरोसा

जस्टिन टूडो ने कहा कि अगर अमेरिका ने टैरिफ लगाए, तो कनाडा कड़ी जवाबी कार्रवाई करेगा। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि कनाडा पहले भी ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान मुक्त व्यापार समझौते पर दोबारा बातचीत करने में सफल रहा था, और इस बार भी अगर जरूरत पड़ी तो कनाडा उसी तरह का कदम उठाएगा। फोर्ड ने यह भी चेतावनी दी कि कनाडा अमेरिकी उत्पादों पर डॉलर-दर-डॉलर टैरिफ लगाएगा। हम रिपब्लिकन-शासित क्षेत्रों को भी निशाना बनाएंगे, फोर्ड ने कहा। कनाडाई नागरिकों को जरूर दर्द होगा, लेकिन अमेरिकी नागरिकों को भी इसका असर महसूस होगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह कनाडा के लिए एक उदाहरण होगा, और अगर ट्रंप कनाडा को निशाना बनाने में सफल होते हैं, तो बाकी देशों को भी यह समझ लेना चाहिए कि वह अगला निशाना हो सकते हैं।

मीका सिंह का वादा: सैफ को हॉस्पिटल पहुंचाने वाले ऑटो ड्राइवर को दैंगे 1 लाख बोलै- उनका काम सराहनीय

मुंबई. ऑटो ड्राइवर भजन सिंह राणा वो शख्स जिसने जख्मी सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल पहुंचाने में मदद की थी। हॉस्पिटल में डिस्चार्ज होने के बाद सैफ ने उनसे मुलाकात की थी। सैफ ने भजन सिंह को न सिर्फ गले लगाया बल्कि 50 हजार का इनाम भी दिया। वहीं अब बॉलीवुड के सिंगर मीका सिंह ने एक्टर सैफ अली खान की जान बचाने वाले ऑटो-रिकशा ड्राइवर भजन सिंह

राणा को इमान देने का वादा किया है। मीका भजन सिंह राणा को 1 लाख देंगे। Mika Singh ने इस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा- मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत के पसंदीदा सुपरस्टार को बचाने के लिए वो कम से कम 11 लाख का इनाम पाने के हकदार है। उनका वीरता से भरा ये काम वास्तव में सराहनीय है! अगर संभव हो, तो क्या आप प्लीज उनसे संपर्क करने की डिटेल्स मेरे साथ

शेयर कर सकते हैं? मैं सराहना के रूप में उन्हें 1 लाख का इनाम देना चाहूंगा।

सैफ अली खान ने दिए 50 हजार रुपये!

एक सूत्र ने बताया कि सैफ अली खान ने ऑटो-रिकशा ड्राइवर को 50 हजार का इनाम दिया है। हालांकि, ड्राइवर ने रुपये-पैसे के बारे में बात नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि पैसे की कोई मांग नहीं थी वो देते तो भी ठीक, नहीं देते तो भी



ठीक था। गौरतलब है कि सैफ पर 15 जनवरी की देर रात को हमलावर ने घर में घुसकर 6 बार चाकू से वार कर दिया था। सैफ ने बच्चों और परिवार को बचाने के लिए आरोपी को सामने से कसकर पकड़ लिया था। खुद को एक्टर के चंगुल से छुड़ाने के लिए आरोपी ने हमला किया था। हमले के बाद उन्हें ऑटो रिकशा से अस्पताल तक ले जाया गया था। ड्राइवर ने उन्हें ना सिर्फ हॉस्पिटल पहुंचाया बल्कि उनसे कोई भी पैसा लेने से भी इंकार कर दिया था।